

समाजवादी बुलेटिन



जाति गिनी
सरकार!

गांधी ने हमें जो रास्ता दिखाया है वही देश
के लिए सही रास्ता है। गांधीवादी रास्ते पर
चलकर हमें समाजवादी सिद्धांतों को साकार
करना है। दुनिया के जितने दुख-दर्द हैं वे
समाजवादी व्यवस्था से ही दूर हो सकते हैं,
दूसरा और कोई रास्ता नहीं है।

मुलायम सिंह यादव

मुलायम सिंह यादव
संस्थापक-संरक्षक, समाजवादी पार्टी



प्रिय पाठकों,
आपकी प्रिय पत्रिका
समाजवादी बुलेटिन बदले
हुए कलेवर में अपने दूसरे
वर्ष में प्रवेश कर चुकी है।
आपके उत्साहवर्धन और
प्रेम के कारण ही हमारा
यह सफर यहां तक पहुंचा
है। हम भरोसा दिलाते हैं
कि हम आपकी उम्मीदों
पर खरा उतरने की अपनी
कोशिशों में कोई कमी नहीं
आने देंगे। कृपया हमेशा
की तरह आगे भी हमारा
मार्गदर्शन करते रहें।
धन्यवाद!

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक
प्रोफेसर रामगोपाल यादव

☎ 0522 - 2235454

✉ samajwadibulletin19@gmail.com

✉ bulletinsamajwadi@gmail.com

Mob:- 9598909095

f /samajwadiparty

समाजवादी पार्टी के लिए

19, विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ से प्रकाशित
अवध पब्लिशिंग हाउस, 8 पान दरीबा, लखनऊ से मुद्रित

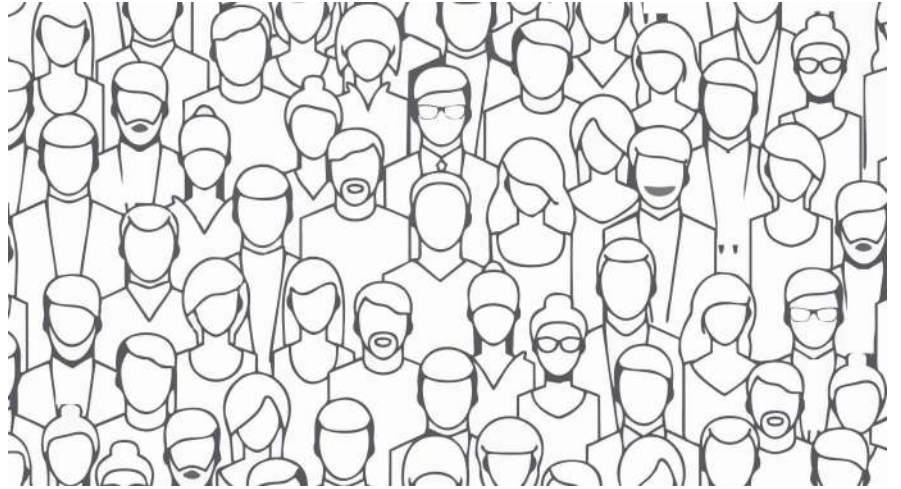
R.N.I. No. 68832/97



सपा कार्यकर्ता कमियों से सबक लें

08 कवर स्टोरी

जाति गिनो सरकार !



बेरोजगारी का अग्निपथ

16



देशव्यापी विरोध के बीच सरकार ने अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती की प्रक्रिया चालू कर दी है। इसके साथ ही पुरानी योजना के तहत होने वाली सारी भर्ती रोक दी गई है, उन नौजवानों का नियुक्ति पत्र भी रोक दिया गया है जो सेना भर्ती की सारी परीक्षाएं पास कर चुके थे और जिनका मेडिकल भी हो गया था।

यूपी लुप्त, सरकार मस्त

04

आपातकाल का अतीत और उसका भविष्य

30

उत्तर प्रदेश में भाजपा राज

यूपी त्रस्त सरकार त्रस्त

बुलेटिन ब्यूरो

भा

जपा की डबल
इंजन सरकार
पांच साल बिना

कोई काम किए सिर्फ समाजवादी सरकार के कामों को ही अपना बताती रही और जब दोबारा सत्ता में आई तो सिर्फ बुलडोजर की धमक से ही अपना कार्यकाल पूरा करना चाहती है। भाजपा सरकार में अपराधों,

महंगाई और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। बेकारी और सरकारी अन्याय भी भाजपा की ही देन है।

उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार में विकास की सभी गतिविधियां अवरुद्ध हैं। अनावश्यक मुद्दों को लेकर भाजपा कलही राजनीति करने की रणनीति पर सरकार और जनता का समय बर्बाद कर रही है। राजकोष

की लूट हो रही है। स्वास्थ्य, शिक्षा को भाजपा सरकार ने बर्हाल किया है। बिजली की आवाजाही से गर्मियों के इन दिनों में जनता लाहि-लाहि कर रही है। भाजपा राज में लोगों को महंगी बिजली और अघोषित कटौती ही मिल रही है।

किसानों और नौजवानों को भाजपा से धोखा मिला है। किसानों की फसलों को



थानों में पीड़ितों की सुनवाई नहीं, महिला सिपाही और सरकारी महिला अधिवक्ता तक दुष्कर्म की शिकार हुई हैं। उत्तर प्रदेश अपराध का अड्डा बन गया है। कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गयी है। लूट-पाट, हिंसा की घटनायें लगातार बढ़ रही हैं। पुलिस प्रशासन के साये में आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता असुरक्षित महसूस कर रही है जबकि अपराधियों के हौसले बढ़ गये हैं।

भाजपा राज में दलित वर्ग की बहन बेटियों से नृशंस अत्याचार और अपराध लगातार बढ़ रहे हैं पर सख्त कदम उठाए जाने के बारे में सिर्फ झूठे आश्वासन और खोखले दावे ही किए जाते हैं।

बेटियां पढ़ना चाहती हैं, अभिभावक पढ़ाना चाहते हैं लेकिन भाजपा सरकार में बेटियां स्कूल कॉलेज नहीं जा सकती हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा तो खूब उछाला जा रहा है पर वास्तविकता में जब बेटी अपराधियों की नज़रों से नहीं बच पा रही है तो फिर बेटियां पढ़ने कहां जा सकती हैं? भाजपा ने उत्तर प्रदेश को जंगलराज बना दिया है।

सरकार भले ही जीरो टॉलरेंस का दावा कर रही हो परन्तु हकीकत में उत्तर प्रदेश अपराध प्रदेश बन गया है। भाजपा की डबल इंजन सरकारों ने लोगों की रोटी और रोजगार तो छीना ही उनका सुख-चैन और इज्जत से जीने के अवसर भी छीन लिए हैं।

उत्तर प्रदेश में ईज ऑफ बिजनेस नहीं ईज ऑफ क्राइम हो रहा है। छिनैती, अपहरण और रंगदारी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। यूपी में इन्वेस्टर्स समिट में उद्योगपतियों के सामने उत्तर प्रदेश की जो छवि प्रस्तुत की गयी उसका सच्चाई से कोई

सम्बंध नहीं है। भाजपा नेता और कार्यकर्ता स्वयं नियम-कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। वे सत्ता के नशे में पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग कर रहे हैं।

भाजपा सरकार की जनविरोधी और गलत नीतियों का खामियाजा पूरा प्रदेश और देश भुगत रहा है। मुख्यमंत्री जी समेत भाजपा के सभी नेता अपनी बात झूठ से शुरू करते हैं और झूठ पर ही खत्म करते हैं। भाजपा सरकार दूसरी बार सत्ता में आने के बाद कुछ और ही कामों में व्यस्त दिखाई देती है जो काम सरकार के नहीं हैं। अपने संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन में पूर्णतया विफल सरकार प्रदेश पर भार स्वरूप है।

भाजपा सरकार में अब वही सुरक्षित है जिस पर सत्ता संरक्षित अपराधियों की निगाह नहीं पड़ी है। अब किसी को भी यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि उसे प्रशासन से सुरक्षा मिल सकती है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) पर नहीं खरीदा गया और न ही नौजवानों को रोजगार मिला। नौकरियों में भर्ती पर घोटाला ही हो रहा है। 70 लाख सालाना नौकरी का वादा करने वाली भाजपा सरकार ने 4 लाख नौकरी देने की घोषणा की पर कहां किसको नौकरी मिली यह विवरण देने से वह मुंह चुराती है। निवेश के नाम पर तमाम झूठे सपने दिखाए जाते हैं पर कहां नए उद्योग लगे और कितने रोजगार सृजित हुए इसका कोई ब्यौरा नहीं मिला है।

उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। हत्या, लूट, बलात्कार के चलते अपराध में उत्तर प्रदेश नम्बर वन बन गया है। महिलाएं-बच्चियां सर्वाधिक असुरक्षित हैं। पुलिस

लोकतंत्र के लिए प्रहसन है

बुलडोजर राज



फोटो स्रोत : गूगल

बुलेटिन ब्यूरो

भाजपा राज में शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लोकतांत्रिक

अधिकारों की लगातार अवमानना की जा रही है। कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है जिसमें वह पूरी तरह विफल साबित हुई है। हर क्षेत्र में अपनी नाकामी छुपाने के लिए सरकार झूठे किस्से-

कहानियां गढ़कर लोगों को गुमराह करने में लगी रहती है।

भाजपा सरकार को बिना वैधानिक प्रावधान के किसी के मकान-दुकान को बुलडोजर से गिराने, अज्ञात के नाम पर निर्दोषों की धर पकड़ करने और समुदाय विशेष को दोषी ठहराने की कोशिशें आदि की अनुमति न तो हमारी संस्कृति न धर्म-

विधान और न ही संविधान देता है।

भाजपा का रवैया अभी भी न्याय संगत नहीं दिखाई देता है। ये कहां का इंसफ है कि जिसकी वजह से देश में हालात बिगड़े और दुनिया भर में सख्त प्रतिक्रिया हुई वह सुरक्षा के घेरे में है और बिना वैधानिक जांच पड़ताल के रावण रूपी 'राक्षसी बुलडोजर' से लोकतंत्र कुचला जा रहा है।



ठोस कदम नहीं उठाया जिससे संकट की स्थिति भयंकर रूप ले रही है।

भारत का संविधान लोकतंत्र, समाजवाद के साथ पंथनिरपेक्षता को मान्यता देता है। यह सभी धर्मों का सम्मान करने का भरोसा देता है। उत्तर प्रदेश गंगा-जमुनी मेल मिलाप का प्रदेश रहा है। परस्पर सद्भाव और सौहार्द के साथ हम सभी त्योहार मनाते हैं और सामाजिक कार्यों में सहभागी रहते हैं। इस एकता को तोड़ने का कोई भी प्रयास अस्वीकार्य है।

भारत का संविधान सभी धर्मों के सम्मान और सुरक्षा की गारंटी देता है। भारत पंथनिरपेक्ष राष्ट्र-राज्य है। यहां किसी धर्म के अनुयायियों की भावनाओं को आहत करने का कोई भी प्रयास निंदनीय है और उसकी

दुर्भाग्य से देश में पिछले कुछ समय से संविधान की मूल भावना के विरुद्ध आचरण होता दिखाई दे रहा है। नफरत और समाज को बंटवारे की कोशिशें होती हैं। इससे परस्पर वैमनस्य और असुरक्षा की भावना को बढ़त मिली है। सरकार को इस संबंध में विशेष सतर्कता बरतते हुए आदर्श राजधर्म का पालन करना चाहिए

यह बात ढकी-छुपी नहीं है कि भाजपा की राजनीति अपने मातृ संगठन आर.एस.एस. के निर्देश पर नफरत और समाज को बांटने की रहती है। हाल में प्रदेश में जो भयंकर अशांति की घटनाएं हुईं उसके पीछे वही राजनीति है। भाजपाई बिगड़े बोल से एक बड़ा समुदाय आहत हुआ। भाजपा सरकार ने इस दुर्भाग्यपूर्ण विवाद की समाप्ति और सम्बन्धित पक्ष के विरुद्ध कोई

स्वीकृति नहीं दी जा सकती है।

भारत और खासकर उत्तर प्रदेश अनेकता में एकता और गंगा-जमुनी सभ्यता-संस्कृति वाला प्रदेश है। यहां बहुधर्मी, बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक, परम्पराओं के लोग रहते हैं। इनके बीच सद्भावना और सौहार्द से ही अमन-चैन बना रह सकता है। परस्पर एक दूसरे की भावनाओं के सम्मान और समन्वय से ही समाज में शांति रह सकती है।

दुर्भाग्य से देश में पिछले कुछ समय से संविधान की मूल भावना के विरुद्ध आचरण होता दिखाई दे रहा है। नफरत और समाज को बंटवारे की कोशिशें होती हैं। इससे परस्पर वैमनस्य और असुरक्षा की भावना को बढ़त मिली है। सरकार को इस संबंध में विशेष सतर्कता बरतते हुए आदर्श राजधर्म का पालन करना चाहिए। समाज के हर वर्ग और सम्प्रदाय के मान सम्मान की रक्षा भाजपा सरकार का नैतिक और संवैधानिक दायित्व है।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने जनता से अपील की है कि वह सब्र से काम ले और शांति का वातावरण बनाने में सहयोग करे। सरकार को भड़काऊ बयानबाजी करने वालों पर कार्रवाई करने में देर नहीं करनी चाहिए ताकि आहत भावनाओं का सम्मान हो सके। साथ ही महामहिम राज्यपाल महोदया को स्थिति का स्वयं संज्ञान लेकर तत्काल कठोर कार्रवाई किए जाने का निर्देश देना चाहिए जिससे प्रदेश में अमनचैन और परस्पर विश्वास बनाये रखने के लिए सरकार की मनमानी व सत्ता के दुरुपयोग पर अंकुश लग सके।



जाति गिनो सरकार!



अरुण कुमार लिपाठी
वरिष्ठ पत्रकार

कें

द्र सरकार जाति जनगणना नहीं कराने जा रही है। यह बात उसने अदालत से लेकर सदन के पटल तक साफ कर दिया है। बल्कि उसने हाल में एनसीईआरटी (राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद) के पाठ्यक्रमों में जो परिवर्तन किया है उससे जाहिर है कि वह मानती ही नहीं कि भारत में जाति की कोई समस्या है। केंद्र सरकार ने भारत की जातिगत संरचना को मानने से ही इंकार कर दिया है। न ही वह जाति तोड़ने के किसी आंदोलन में यकीन करती है।

समाजशास्त्र और इतिहास के पाठ्यक्रमों से जाति की चर्चा को न्यूनतम कर देने या खत्म कर देने का प्रयास यह बताता है कि उसने भारतीय समाज की धर्म आधारित विभाजनकारी भावना को यथार्थ मान लिया है और जाति आधारित सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक यथार्थ को परदे से ढके रहना चाहती है। बल्कि यूं भी कह सकते हैं कि वह

सांप्रदायिक विभेद की भावना से जाति की सच्चाई को भुलाए रखना चाहती है। हालांकि अभी उसका यह साहस नहीं है कि वह आरक्षण को खत्म कर दे। हालांकि तेजी से हो रहे निजीकरण का आर्थिक लक्ष्य तो है ही, उसी के साथ आरक्षण खत्म करने का सामाजिक लक्ष्य भी है।

ऐसे माहौल में बिहार ने एक रास्ता दिखाया है और उसे दूसरे राज्यों को देखना चाहिए। बिहार में मौजूदा सरकार के नेतृत्व में सभी दलों ने मिलकर जाति जनगणना कराने का फैसला लिया है और केंद्र सरकार से यह अनुमति पा ली है कि उसे कोई आपत्ति नहीं है। अगर विभिन्न राज्य चाहें तो अपने अपने ढंग से यह काम करा सकते हैं। बिहार की जाति जनगणना का फैसला अपने आप में चौंकाने वाला है। क्योंकि इस फैसले में सत्तारूढ़ जनता दल(यू) के प्रमुख प्रतिद्वंद्वी राष्ट्रीय जनता दल ने भी खुलकर साथ दिया है। मजबूरी में भारतीय जनता पार्टी को भी नानुकर करके साथ आना पड़ा है। यह अपने



फोटो स्रोत : गूगल

आप में एक अंतर्विरोध है जो साफ दिखाई पड़ रहा है कि हिंदुत्व की ताकतों के साथ सामाजिक न्याय की शक्तियों के रिश्ते सहज नहीं हैं। जब तक सामाजिक न्याय की ताकतें सक्रिय रहेंगी तब तक भाजपा के लिए पूरे समाज को हिंदुत्ववादी बनाना कठिन होगा। बिहार में हाल में सबसे उग्र रूप में चला अग्रिम योजना विरोधी आंदोलन भी इसका प्रमाण है।

उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी जाति आधारित जनगणना की मांग जोरशोर से उठाती रही है। अगर समाजवादी पार्टी सत्ता में आई होती तो शायद वह काम उसी तरह या उससे अच्छे तरीके से हो जाता जैसा कि बिहार में होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने प्रदेश की दलित और ओबीसी की विभिन्न जातियों के संगठनों के साथ एक इंद्रधनुषी गठबंधन इसलिए बनाया था कि वह इस काम को संपन्न कर सके। सामाजिक न्याय

सामाजिक न्याय का यह एजेंडा वास्तव में समाज में जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी भी सुनिश्चित करेगा और साथ ही सांप्रदायिक विभाजन को भी पाटेगा। सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग और समाज को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के चलते फिर भाजपा सत्ता में आ गई

का यह एजेंडा वास्तव में समाज में जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी भी सुनिश्चित करेगा और साथ ही सांप्रदायिक विभाजन को भी पाटेगा। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग और समाज को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के चलते फिर भाजपा सत्ता में आ गई और उसे दलितों और ओबीसी जातियों को बहकाने का मौका मिल गया।

लेकिन भाजपा की सोशल इंजीनियरिंग की हकीकत बयां करते हुए फ्रांसासी समाजशास्त्री क्रिस्टोफर जैफ्रां लिखते हैं कि भाजपा और उसके ताकतवर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भले ही दावा करें कि उनकी पार्टी ने विधानसभा से लेकर कैबिनेट तक सामाजिक न्याय किया है बल्कि हकीकत यह है कि यह शासन पूरी तरह से सवर्णों के प्रभुत्व वाला शासन है। भाजपा के विधायकों में उच्च जातियों की संख्या 43

प्रतिशत है। जबकि उनकी आबादी 20 प्रतिशत है। दूसरी ओर प्रदेश में ओबीसी आबादी 50 प्रतिशत से ज्यादा है लेकिन उसे भाजपा की ओर से विधानसभा में महज 33 प्रतिशत प्रतिनिधित्व मिला है। इन 43 प्रतिशत विधायकों में 17 प्रतिशत ब्राह्मण और 16 प्रतिशत राजपूत हैं। जबकि उनकी आबादी क्रमशः 10 प्रतिशत और 7 प्रतिशत है।

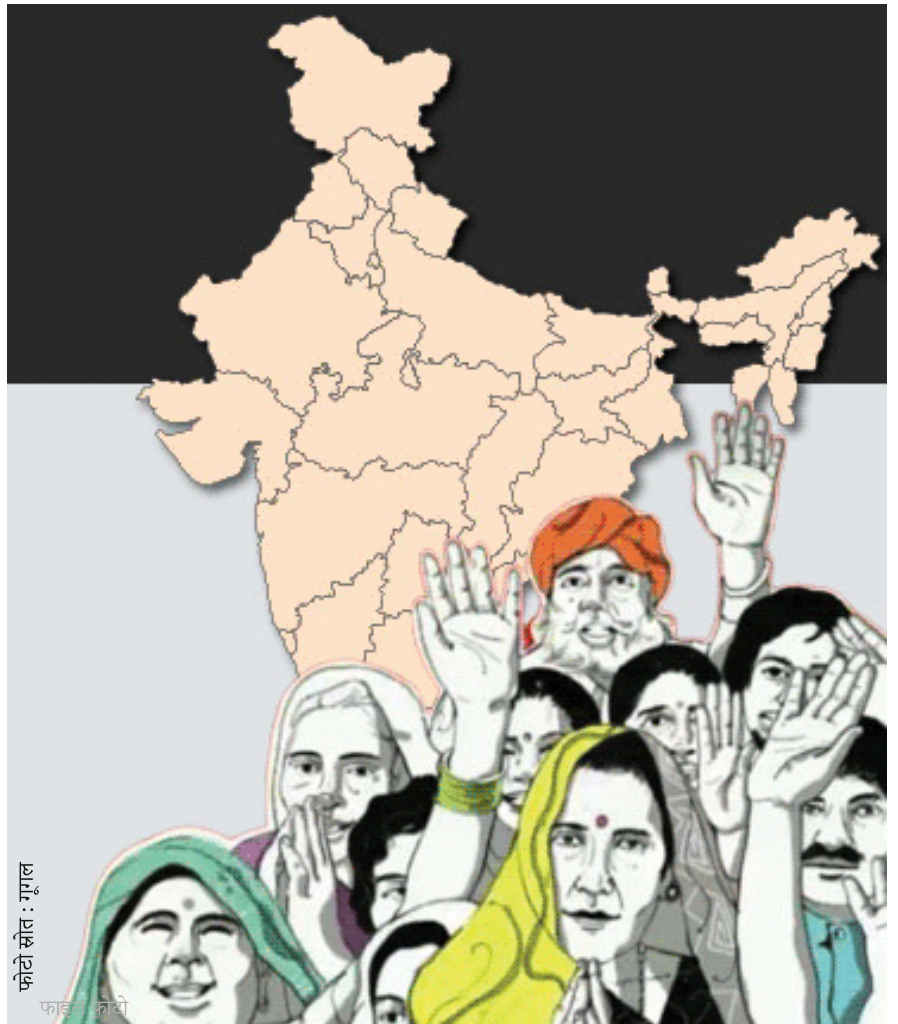
अब जरा योगी मंत्रिमंडल की संरचना पर गौर कीजिए। ओबीसी मंत्रियों की संख्या 20 है। यानी मंत्रिमंडल का 38.8 प्रतिशत। लेकिन उनमें से ज्यादातर के पास राज्य मंत्री का प्रभार है। जबकि ऊंची जातियों के मंत्रियों की संख्या 21 है और उनमें से ज्यादातर के पास कैबिनेट है। चुनाव में हारे हुए ओबीसी नेता केशव प्रसाद मौर्य भले उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं लेकिन उनसे पीडब्लूडी मंत्रालय लेकर ब्राह्मण मंत्री जितिन प्रसाद को दे दिया गया है। राजपूत मुख्यमंत्री के पास 34 विभाग हैं। उनका वित्त मंत्री खली है, पीडब्लूडी मंत्री ब्राह्मण है, स्वास्थ्य मंत्री ब्राह्मण है, कृषि मंत्री बनिया है, नगर विकास मंत्री ब्राह्मण हैं और उच्च शिक्षा मंत्री भी ब्राह्मण हैं। उसके विपरीत ओबीसी मंत्रियों के पास पशुपालन, जलशक्ति, मत्स्य पालन और लघु व मझौले उद्यम के मंत्रालय हैं। एक दलित है मंत्रिमंडल में और उसके पास भी महिला और बाल कल्याण जैसा अपेक्षाकृत कम महत्व वाला विभाग है। अल्पसंख्यकों का तो प्रतिनिधित्व ही महज 3.7 प्रतिशत है। उनका एक ही मंत्री है।

इसके विपरीत 2012 से 2017 तक अखिलेश यादव के मंत्रिमंडल में सामाजिक विविधता और न्याय का ज्यादा ध्यान रखा

गया था। यह बात गिल्स बर्नियर्स अपनी पीएचडी थीसिस में रखते हैं। वे कहते हैं कि उस समय राजनीति ज्यादा समावेशी थी और समाज के सभी हिस्सों का समुचित प्रतिनिधित्व था उनके विधायकों और मंत्रियों में। अखिलेश यादव के मंत्रिमंडल में 22 प्रतिशत मंत्री मुस्लिम समुदाय से थे। उनके मुस्लिम विधायकों की संख्या 17 प्रतिशत थी और ओबीसी विधायकों की संख्या 27 प्रतिशत थी। सवर्ण विधायकों की संख्या 26 प्रतिशत थी। उनके मंत्रिमंडल में सवर्णों का प्रतिनिधित्व 33 प्रतिशत था तो ओबीसी प्रतिनिधित्व 31 प्रतिशत था। जाति जनगणना रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो विकल्प प्रस्तुत किया है वह है सोशल इंजीनियरिंग का सिद्धांत।

उसका मकसद यह है कि समाज में जाति और वर्ण व्यवस्था बनी रहे और राजनीति में प्रतीकात्मक रूप से सभी को अपने प्रतिनिधित्व का नकली अहसास होता रहे। दूसरी बात यह है कि अगर अगर हिंदू समाज ने यह स्वीकार कर लिया कि उसके भीतर जाति की ऊंच नीच व्यवस्था है तो उसे कैसे एकजुट करके अल्पसंख्यकों के विरुद्ध गोलबंद किया जा सकेगा।

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का समाज के हिंदूकरण का जो अभियान है वह उसी समय ध्वस्त हो जाता है जब यह मान लिया जाता है कि हिंदू समाज के भीतर धर्म आधारित असमानता और अन्याय है। जाति जनगणना उसका सबसे प्रकट प्रमाण प्रस्तुत करेगी इसलिए संघ परिवार और भाजपा



जातीय जनगणना ही सामाजिक न्याय की कसौटी

बुलेटिन ब्यूरो

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार पिछड़ी जातियों की जातिवार जनगणना कराए ताकि उनकी वास्तविक जनसंख्या जनता के सामने आ सके। उन्हें जनसंख्या के आधार पर सत्ता, सरकार व नौकरियों सहित सभी क्षेत्रों में समानुपातिक हिस्सेदारी दे दी जाए। इस प्रकार सामाजिक न्याय को पूरी तरह लागू किया जा सकता है और किसी भी वर्ग में कोई सन्देह नहीं पैदा होगा। नहीं तो पिछड़े वर्गों में लगातार असंतोष बढ़ता जाएगा। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ऐसा न करके पिछड़े वर्गों के वास्तविक आंकड़े को छिपाना चाहती है और पिछड़े वर्गों को सत्ता के अधिकार व सम्मान से वंचित रखना चाहती है। भाजपा सरकार पिछड़े वर्गों को धोखा दे रही है। सबको मालूम है कि बिना पिछड़ी जातियों की वास्तविक जनसंख्या आए योजनाओं का लाभ उन तक नहीं पहुंचाया जा सकता है। ओबीसी की वास्तविक जनसंख्या स्पष्ट न होने से उनके हक में कोई सकारात्मक आदेश नहीं हो पाता। सरकारें जानबूझकर पिछड़ों के अधिकारों के मामलों को

दबा देती हैं। 1931 में अंतिम बार जातिगत जनगणना कराने के बाद आज तक केन्द्र सरकार ने ओबीसी की जनगणना कराना उचित नहीं समझा।

2011 में एससी, एसटी, धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग के साथ-साथ ट्रांसजेंडर व दिव्यांग की जनगणना कराकर उनकी जनसंख्या की घोषणा 15 जून, 2016 को ही कर दी गयी थी लेकिन पिछड़ी जातियों की नहीं की गई थी। यूपीए-2 में कांग्रेस सरकार में पिछड़े वर्गों की जातीय जनगणना कराने का सवाल लोकसभा में सपा संस्थापक माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी, माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी तथा माननीय शरद यादव जी ने जोरशोर से उठाया था तथा लोकसभा में सभी पिछड़े वर्गों के सांसदों ने समर्थन किया था। सरकार ने जातीय जनगणना कराने का आश्वासन भी दिया लेकिन जब जनगणना करायी गयी तो ओबीसी को दरकिनार कर दिया गया।

कांग्रेस के ही रास्ते पर चलते हुए मोदी सरकार भी ओबीसी की जातिगत जनगणना कराने से मुकर गयी। सपा ने नारा दिया था

उससे भाग रही है। बल्कि जाति जनगणना यह भी प्रमाण प्रस्तुत करेगी कि भारत में मुस्लिम समाज भी जाति व्यवस्था से ग्रसित है। ईसाई समाज भी जाति व्यवस्था से ग्रसित है और सिख समाज भी उससे परे नहीं है। भारत के अकादमिक विद्वानों, नीतिकारों और सामाजिक न्याय से जुड़े राजनेताओं ने बार बार कहा है कि सबलीकरण और जनकल्याण की सरकारी योजनाएं तब तक

जब जाति जनगणना होगी तो यह भी पता चलेगा कि पिछड़ी जातियां अल्पसंख्यकों में भी हैं। इससे उन्हें भी योजनाओं का लाभ मिलेगा। इस प्रकार समाज में गैर धार्मिक गोलबंदी भी होगी जो नाजायज और नफरत भरी गोलबंदी को तोड़ देगी।

कि जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। हर वर्ग को जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व, भागीदारी व हिस्सेदारी देना ही संवैधानिक व्यवस्था व मौलिक अधिकार तथा नैसर्गिक न्याय के दायरे में आता है।

पिछड़े वर्गों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक सुरक्षा व उनके अधिकारों को संरक्षण देना सरकारों की संवैधानिक जिम्मेदारी है। भाजपा सरकार उस जिम्मेदारी से हट रही है।



सफल नहीं हो सकती और न ही अपने लक्ष्य तक पहुंच सकती हैं जब तक जाति आधारित जनगणना न हो।

लेकिन मुश्किल यह है कि भाजपा के विचारक और सिद्धांतकार यह स्वीकार करने को तैयार ही नहीं हैं कि भारत में जाति व्यवस्था का अन्याय है। उनके प्रमुख विचारक दीन दयाल उपाध्याय मानते हैं कि हिंदू समाज की जातियां तो वैसी हैं जैसे

किसी मनुष्य के हाथ पैर होते हैं। वे उसके अंग प्रत्यंग हैं। इसलिए उन्हें तोड़ने की बात करना उस समाज के हाथ पैर तोड़ने की बात करने जैसा है। संघ और भाजपा के लोग विनायक दामोदर सावरकर का बड़ा गुणगान करते हैं लेकिन वे उनके सामाजिक न्याय संबंधी विचारों पर बात नहीं करते। वे उनके हिंदुत्व वाले विचार पर बात करते हैं। यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि

सावरकर के विचार जाति के मामले में डा आंबेडकर के विचारों से मिलते थे। लेकिन संघ परिवार अपने समाज की बुराई को देखना नहीं चाहता। उसे सिर्फ दूसरे समाज की बुराई दिखती है और वह पूरा विमर्श उसी पर खड़ा करना चाहता है।

डा आंबेडकर की मूर्ति पर माला पहनाने और उनको प्रातः स्मरणीय बताने में संघ परिवार आगे रहता है। लेकिन वह उनके सामाजिक



फोटो स्रोत : गूगल

परिवर्तन के दर्शन को खामोशी से ठंडे बस्ते में डाले रहता है। उसे आंबेडकर इसलिए चाहिए ताकि दलितों का हिंदूकरण किया जा सके। न कि दलितों को सामाजिक न्याय दिलाया जा सके और उन्हें हिंदू धर्म के अन्यायी ढांचे से मुक्त किया जा सके।

डा राम मनोहर लोहिया ने लखनऊ की ब्राह्मण बनिया राजनीति पर तमाम हमले किए थे। लेकिन उनका समय ऐसा था कि उनकी पार्टी में भी वही लोग हावी थे। काशीराम ने उत्तर प्रदेश को ब्राह्मणवाद का पालना कहा था। उन्होंने उस पालने को हटाने के लिए बड़ा प्रयास किया और एकहद तक उसे चुनौती भी दी। लेकिन अयोध्या आंदोलन को सफलतापूर्वक चलाने और उसके बाद मथुरा, काशी और आगरा समेत तमाम आंदोलनों की तैयारी में लगा संघ परिवार सामाजिक न्याय के उस आंदोलन को खा गया। वह प्रदेश का बुरी तरह

जाति जनगणना होने के बाद ओबीसी की आबादी 50 प्रतिशत से ज्यादा भी निकल सकती है उससे आरक्षण की 50 प्रतिशत की सीमा रेखा हटाने की मांग उठेगी। बल्कि यह मांग यहीं तक सीमित नहीं रहेगी। डायवर्सिटी की मांग भी उठेगी

सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कर चुका है।

देश के तीन सबसे गरीब जिले श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर उत्तर प्रदेश में हैं। वहां गरीबी की दरें क्रमशः 74.38, 71.88 और 69.45 प्रतिशत हैं। पूरे प्रदेश में गरीबी की दर 37 प्रतिशत है। वहां निरक्षरता का औसत 27 प्रतिशत है। नीति निर्माताओं के पास यह आंकड़े होने चाहिए कि प्रदेश में गरीबी, निरक्षरता और पढ़ाई लिखाई के जातिवार आंकड़े क्या हैं। ताकि ऐसे कार्यक्रम बनाए जा सकें जिनमें समाज के उन हिस्सों पर विशेष ध्यान दिया जा सके। लेकिन इस सरकार की मुश्किल यह है कि जब जाति जनगणना होगी तो यह भी पता चलेगा कि पिछड़ी जातियां अल्पसंख्यकों में भी हैं। इससे उन्हें भी योजनाओं का लाभ मिलेगा। इस प्रकार समाज में गैर धार्मिक गोलबंदी भी होगी जो नाजायज और नफरत भरी गोलबंदी को तोड़ देगी।

जाति जनगणना होने के बाद ओबीसी की आबादी 50 प्रतिशत से ज्यादा भी निकल सकती है उससे आरक्षण की 50 प्रतिशत की सीमा रेखा हटाने की मांग उठेगी। बल्कि यह मांग यहीं तक सीमित नहीं रहेगी। डायवर्सिटी की मांग भी उठेगी जिसके तहत सरकारी क्षेत्र में खत्म होती नौकरियों के बीच निजी क्षेत्र में भी दलितों और पिछड़ों के आरक्षण की मांग उठेगी। जाति जनगणना भारतीय समाज की सामाजिक और आर्थिक असमानता मिटाने का मजबूत आधार प्रदान करेगी और उससे भारतीय समाजवाद का नया सिद्धांत निकलेगा।

लेकिन इस देश का हिंदुत्ववादी प्रभु वर्ग और आर्थिक शक्तियों को अपनी मुट्ठी में समेटे कारपोरेट वर्ग नहीं चाहता कि भारतीय समाज में सामाजिक न्याय का आलोड़न हो और यह समाज संविधान के संकल्प के मुताबिक समतामूलक बने। उनके लिए गैरबराबरी, अशिक्षा और गरीबी पर आधारित समाज ही बेहतर है। उससे उसे काम भर को मैनेजर मिल जाएंगे, अफसर मिल जाएंगे और फिर बड़ी संख्या में सिविलियन गार्ड, धोबी, सफाई कर्मी और

ड्राइवर जैसे लोग मिल जाएंगे।

अगर ऐसा न होता तो अग्रिम योजना लाकर वह किसान जातियों की आकांक्षाओं पर तुषारापात न करते। वे सेना का आधुनिकीकरण करना चाहते हैं, अर्थव्यवस्था का कम्प्युटीकरण और डिजिटलीकरण करना चाहते हैं लेकिन समाज को मंदिरों और मस्जिदों में भटकाते हुए, उसकी विभिन्न जातियों को एक दूसरे से लड़ाते हुए उसे मध्ययुग में ही रखना चाहते हैं। अगर हो सके तो उसे प्राचीन युग में पहुंचा देना चाहते हैं।

दलित और ओबीसी समाज के सामने यह चुनौती है कि वह असमानता पर आधारित धार्मिक विमर्श को अपनाता है या फिर संविधान सम्मत समता के विमर्श को लेकर आगे चलता है। अगर उसने संविधान से प्रेरणा लेकर समता का रास्ता चुना तो वह जाति जनगणना के आंदोलन की ओर

जाएगा। वह आंदोलन देश की सर्वाधिक आबादी वाले प्रदेश से एक नई पहल करेगा। जाहिर सी बात है कि बिहार ने इस मामले में लीड ले ली है लेकिन अगर उत्तर प्रदेश ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो दक्षिण भारत से भी इस दिशा में पहल होगी। शायद इससे खतरनाक दिशा में जा रही राजनीति एक नई करवट ले सकती है। यह राजनीति 2024 के चुनाव को भी प्रभावित करेगी, विपक्षी एकता का एक आधार बनाएगी क्योंकि इससे पहले कांग्रेस, सपा, माकपा, भाकपा, डीएमके राजद समेत कई दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने प्रतिनिधित्व करते हुए जाति जनगणना की मांग कर चुके हैं। उन्होंने विचार करने का आश्वासन भी दिया था। आज फिर से उस मामले को उठाने का समय आ गया है।

(यह लेखक के अपने विचार हैं)



बेरोजगारी का अग्निपथ



दे

शव्यापी विरोध के बीच सरकार ने अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती की प्रक्रिया चालू कर दी है।

इसके साथ ही पुरानी योजना के तहत होने वाली सारी भर्ती रोक दी गई है, उन नौजवानों का नियुक्ति पत्र भी रोक दिया गया है जो सेना भर्ती की सारी परीक्षाएं पास कर चुके थे और जिनका मेडिकल भी हो गया था।

ऐसे कोई दस बीस नहीं, लाखों नौजवान हैं। गांवों के बहुत ही सामान्य आय वाले परिवारों के ये बच्चे कब से और किस बेचैनी से फौज की नौकरी की चाहत रखते हैं और चुनाव के लिए कितनी मुश्किल ट्रेनिंग करते हैं यह सरकार या प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को नहीं

मालूम है ऐसा भी नहीं है। सेना में ही भर्ती के कितने स्तर हैं जिनके लिए ये बच्चे सुबह लम्बी दौड़ लगाने से लेकर भारी फीस देकर कई तरह की कोचिंग और ट्रेनिंग करते हैं। अगर यह बच्चा चुन लिया गया तो सिर्फ उसका ही नहीं पूरे परिवार और आने वाली पीढ़ी का जीवन बदल जाता है जो फौज में मिलने वाली सुविधाओं और वेतन भत्ते के अलावा पेंशन से आराम से गुजारा करता है।

फौजी अनुशासन, देश दुनिया की जानकारी, शिक्षा-स्वास्थ्य की महत्ता का ज्ञान और उसके लिए जरूरी साधनों की उपलब्धता फौजी का ही नहीं पूरे परिवार का जीवन बदल देती है। फौजी देश की कैसी और कितनी सेवा करता है और समाज उसका इतना मान क्यों करता रहा है यह



अरविन्द मोहन

लेखक, वरिष्ठ पत्रकार

बताने की चीज नहीं है।

भर्ती की यह प्रक्रिया पूरे हफ्ते के विरोध और चौतरफा उग्र प्रतिक्रिया के बाद शुरू हुई है। सरकार ने योजना बनाते हुए न तो इस पर किसी सम्बद्ध पक्ष से बात की ना ही उसने बाद की बातचीत में भी विपक्ष या विरोध करने वाले नौजवानों के प्रतिनिधियों से किसी किस्म का संवाद किया। उसने अपनी तरफ से तैयारी पूरी रखी (हालांकि वह हिंसक प्रतिक्रिया के मूड को भांपने में चूकी) और नए-पुराने फौजी अधिकारियों की टीम को इस योजना के पक्ष में बोलने की ड्यूटी में लगाया और पूरी मीडिया को अपनी प्रचार योजना का हिस्सा बनाया।

इतना ही नहीं उसने देश की रक्षा और ग्रामीण नौजवानों के रोजगार के नाम पर किए अपने इस भद्दे मजाक के प्रति उपजी नाराजगी को कम करने के लिए दनादन कई और रियायतें और योजनाएं घोषित कीं।

भाजपा की राज्य सरकारों ने ही नहीं, उसके पार्टी पदाधिकारियों ने (किसी ने चार साल में रिटायर अग्निवीरों को भाजपा दफ्तर में गार्ड रखने की घोषणा की तो किसी ने उन्हें प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन बनाने का आश्वासन दिया) भी रिटायर्ड अग्निवीरों के लिए सपने दिखाने वाली योजनाएं और आरक्षण की घोषणा की। यह पहली ऐसी योजना है जिसमें चार साल के रोजगार में काम क्या होगा इसकी जगह चार साल बाद के कामों की ही चर्चा हुई और अगर बेरोजगारों को यह जले पर नमक छिड़कने जैसा लगा तो कुछ भी अस्वाभाविक नहीं था।

अचरज नहीं कि योजना की घोषणा होते ही देश भर में तूफान मच गया। नौजवान अपने को ठगा महसूस करके अपना गुस्सा रेल और सड़क परिवहन के साधनों पर उतारने लगे। तीन-चार दिन के बाद यह गुस्सा कुछ हल्का हुआ या नहीं पर नौजवानों को भी

लगा कि गुस्सा निकालने का यह तरीका गलत है और इसने उनके आन्दोलन और नाराजगी के प्रति समाज की सामान्य सहानुभूति को काफी कम कर दिया है। इसने भाजपा के लोगों, सरकार का भोंपू बन गई मीडिया और सरकारी निर्देश पर इस योजना के पक्ष में बोलने उठे नए पुराने फौजी अधिकारियों को कुछ आधार भी दिया क्योंकि हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं है और फौज में जाने की चाहत रखने वालों के इतने अनुशासनहीन व्यवहार की आलोचना करना आसान था।

इन युवाओं के लिए यह नई योजना तो एक सपने का मरना ही नहीं बल्कि आगे का जीवन अन्धकार मय दिखने का माध्यम है। फौज और देश की सुरक्षा किस तरह चौपट होगी उसकी चिंता शायद इन नौजवानों को उतनी नहीं होगी जितनी होनी चाहिए लेकिन अपने भविष्य की चिंता ही आग भड़काने के



फोटो स्रोत : गूगल



फोटो स्रोत : गूगल

लिए काफी थी। मामला सिर्फ फौज और बेरोजगारी का नहीं है। जिस तरह साल में दो करोड़ रोजगार का वायदा किया गया था उससे भी अब निराशा होने लगी है क्योंकि आठ साल बीत चुके हैं और बात जहां-तहां संविदा वाली नियुक्तियों से आगे बढ़ ही नहीं रही है। सरकार बस झुनझुना पकड़ा रही है। आरक्षण का भी पूरा नाश 'पिछड़ा प्रधानमंत्री' ने कर रखा है।

रोजगार के मोर्चे पर युवाओं के बीच निराशा के इस माहौल के दौर में फौज की सारी पुरानी भर्ती व्यवस्थाओं और चालू प्रक्रियाओं को समाप्त करके यह अजीबोगरीब नामधारी योजना आई जिसमें रोजगार और फौजी मजबूती की बात कम, रिटायरमेंट और उसके बाद क्या होगा उसकी चर्चा ही ज्यादा है। जिसके मुताबिक अग्रिमपथ योजना से चुने गए जवानों को चार

रोजगार के मोर्चे पर युवाओं के बीच निराशा के इस माहौल के दौर में फौज की सारी पुरानी भर्ती व्यवस्थाओं और चालू प्रक्रियाओं को समाप्त करके यह अजीबोगरीब नामधारी योजना आई जिसमें रोजगार और फौजी मजबूती की बात कम, रिटायरमेंट और उसके बाद क्या होगा उसकी चर्चा ही ज्यादा है

साल के लिए नियुक्त करने के बाद उनमें तीन चौथाई को रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। 25 साल की उम्र में बेरोजगार इन युवाओं का भविष्य बहुत बड़ा सवाल है।

इतना ही नहीं, मात्र छह महीने की ट्रेनिंग को सेना का हर जानकार कम मानता है। सेना के उपकरणों की बुनियादी समझ और संचालन के लिए कुल 10000 घंटे की ट्रेनिंग को जरूरी माना जाता है जो इन अग्रिमपथियों को नहीं मिलेगी। मात्र चार साल की नौकरी फौज के बुनियादी चरित्र को भी बदलेगी क्योंकि देश सेवा और फौज की सेवा की जगह जवानी में आने वाली बेरोजगारी की चिंता सर्वोपरि होगी।

योजना को लेकर बवाल मचने पर सरकार की तरफ से कई तरह की सफाई दी गई, कई नई रियायतें और आरक्षण घोषित हुए। इसी क्रम में एक बड़ी सच्चाई सामने आ गई कि

इस योजना का उद्देश्य सेना के खर्च में ज़ीडीपी का एक फीसदी से ज्यादा कटौती करना है, पर यह नहीं बताया गया कि सेना का आकार-प्रकार भी छोटा किया जाएगा। कई दिनों बाद जब रक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सामने आए तो कहा कि भविष्य के युद्ध बहुत अलग ढंग के होंगे। अब युद्ध फौज नहीं तो कौन लड़ेगा, यह सवाल किसी ने नहीं पूछा लेकिन साफ है कि फौज का बजट ही नहीं आकार भी घटाना है।

यह भी लगता है कि सेना के पास देश में जो लाखों एकड़ कीमती जमीन है उस पर बाजार की नजर है। रेलवे की ऐसी जमीन को लेकर तो बड़ा खेल शुरू हो चुका है। अभी तक कैट इलाके की जमीनें बची हैं। बाजार वहां भी अपने लिए सम्भावना देख रहा है और यह सरकार आंख बन्द करके बाजार के इशारे पर नाच रही है- भले ही माहौल बनाने के लिए वह नाम चाहे राष्ट्रवाद का ले या हिन्दू स्वाभिमान और संस्कृति का या फिर कथित वंशवाद विरोध का।

भाजपा के ही सांसद वरुण गांधी के अनुसार साल 2019 में हर घंटे एक बेरोजगार ने आत्महत्या कर ली। ठेके पर काम करने का चलन इस सरकार ने नहीं शुरू किया है लेकिन जिस बेशर्मी से यह शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी क्षेत्रों में भी (जहां पूर्णकालिक रोजगार रहा है और आगे भी जरूरत रहेगी ही) संविदाकर्मियों की नियुक्ति कर रही है वह बताता है कि यह अग्निवीर योजना भी बुनियादी रूप से सेना के लिए संविदाकर्मियों नियुक्त करना ही है।

वर्ष 2014 में देश में सरकारी कर्मचारियों में संविदा कर्मियों की संख्या 43 फीसदी थी जो 2018 में बढ़कर 59 फीसदी हो गई। इस रफ्तार से यह संख्या अभी ही 65 फीसदी को



पार कर गई होगी। अगर फौज की यह योजना और रेलवे के निजीकरण की यही रफ्तार रही तो नब्बे फीसदी पार करने में देर नहीं होगी। फिर वित्तीय बोझ के साथ आरक्षण, पेंशन, ग्रेज्युटी और कर्मचारी के परिवार के सदस्य को नौकरी देने जैसी चीजों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। निजी क्षेत्र में काम का मतलब श्रम कानून से लेकर पचासों दूसरी उन सुविधाओं का नाश हो जाना है जिसकी लड़ाई भारत और दुनिया के श्रमिक सैकड़ों साल से लड़ते रहे हैं। आरक्षण और निजी क्षेत्र का मेल वैसे भी नहीं है।

इस सरकार ने जानबूझकर जिस तरह से सरकारी पदों को खाली रखा है, पुराने लोगों को एक्सटेंशन देकर काम चला रही है उसमें उसकी यह मंशा भी साफ दिखती है कि आने वाले समय में सेना के अग्निवीरों की तरह जाने कितने प्रकार के 'वीर' लाए जाएंगे। अभी भी सरकार के करीब साठ लाख पद खाली पड़े हैं जिनमें केन्द्र की रिक्तियों की संख्या ही नौ लाख से ज्यादा है। सबसे ज्यादा रिक्तियां राज्य की पुलिस एजेंसियों में हैं क्योंकि मोदी सरकार यह मानती है कि वे तो अपना काम चला लेते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों की रिक्तियों की चर्चा के साथ

यह भी जोड़ना चाहिए कि खुद उनका भी अस्तित्व दांव पर है और कथित नवरत्न कम्पनियों की हालत बिगाड़ी जा रही है। स्वास्थ्य और शिक्षा से सरकार तेजी से हाथ खींच रही है।

अग्निवीर योजना चालू हो जाने के बावजूद उसके विरोध में कमी नहीं दिखती। शुरू के एक दो दिन संशय में रहने के बाद लगभग सभी विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को उठा लिया है। नौजवानों की तरफ से भी हिंसा एकदम थम गई है और किसान युनियन समेत कई दूसरे संगठनों का साथ मिलने लगा है। विपक्ष द्वारा संसद में इस पर चर्चा की मांग उठने लगी है। यह सही है कि यह योजना आधिकारिक आदेश से शुरू हुई है और कोई नीतिगत या विधायी फैसला नहीं है। बिना चर्चा के कानून लाना और फैसले करना अनुचित है। मोदी सरकार बार-बार ऐसा कर रही है। सेना में नियुक्ति का मसला सारे देश की सुरक्षा और लाखों लोगों के जीवन से जुड़ा है। इस पर आई यह नीति हर तरह से नुकसानदेह है।

(यह लेखक के अपने विचार हैं)





सेना के पीछे छिप रही है सरकार!



प्रेम कुमार

वरिष्ठ पत्रकार

मो

दी सरकार की सेना में भर्ती की विवादित अग्निपथ योजना ने देश के इतिहास में पहली बार यह वाक्या देखा जिसमें सेना के तीनों अंगों के सैन्य प्रमुखों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देश के नौजवानों को चेताया। यह फटकार कितना सही है और कितना गलत- इसके मूल्यांकन का नजरिया अपना-अपना हो सकता है।

फिर भी जो बात लीक से हटकर है, अनोखी है और दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में परंपरा से अलग है, उसकी चर्चा होना जरूरी है।

प्रेस कान्फ्रेंस में दांव पर रख दी सेना की साख

सेना के इन तीनों प्रमुखों ने एक ऐसी घोषणा कर दी जिस पर अंतिम फैसला केंद्र सरकार लेती है। यानी यह विषय ही पूरी तरह से

उनके वश में नहीं है। थल सेना, वायुसेना और नौ सेना प्रमुखों ने घोषणा की कि अग्निपथ योजना वापस नहीं ली जाएगी। क्या इसी घोषणा के लिए ये प्रमुख प्रेस कान्फ्रेंस में आए थे?

अगर हां, तो उस स्थिति में उनकी विश्वसनीयता का क्या होगा जब परिस्थितिवश मोदी सरकार मजबूरी में यह योजना वापस ले लेगी? यह सवाल इसलिए



फोटो स्रोत : गूगल

अग्निपथ योजना की घोषणा भी सेना के तीनों अंगों के प्रमुख ही करते या फिर यह अवसर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस मनोज नरवणे को मिलता। मगर, ऐलान तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। यह स्पष्ट है कि अग्निपथ योजना मोदी सरकार की पहल है। यही वजह है कि इस योजना की बाबत बात करने से पहले सेना के तीनों अंग प्रमुखों को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करनी पड़ी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यह बताने क्यों नहीं सामने आए कि

● अग्निपथ योजना रोल बैक नहीं होगी

● अग्निवीरों के वीरगति प्राप्त होने की स्थिति में आश्रितों को मुआवज़ा 44 लाख नहीं 1 करोड़ मिलेगा।

● अनुशासन तोड़ने वाले नौजवानों को अग्निपथ योजना में स्थान नहीं मिलेगा।

● अग्निपथ योजना में शामिल होने के लिए यह घोषित करना होगा कि उसने ट्रेन नहीं जलायी हैं, आगजनी नहीं की है या उपद्रव में हिस्सा नहीं लिया है

असैनिकों को सेना का अनुशासन बताने की जरूरत क्यों पड़ी?

आखिर सेना के तीनों अंगों के प्रमुखों को सेना के अनुशासन को सार्वजनिक रूप से बताने की जरूरत क्यों पड़ी? जो नौजवान अभी सेना के अंग नहीं हुए हैं उन्हें भी पता है कि थाने की पुलिस डायरी में अगर उनका नाम पाया गया तो वे सेना के लिए अयोग्य ठहराए जा सकते हैं। फिर भी इसे दोहराने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी।

चूंकि देश में अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की होने जा रही भर्ती का भारी विरोध हो रहा है और इस विरोध में रेल

जलाना, उपद्रव करना, तोड़-फोड़ सब शामिल हैं तो क्या इन्हें शांत करने के लिए अनुशासन का डंडा दिखाया जा रहा था? अगर ऐसा है, तो एक बार फिर सवाल उठता है कि जो काम सरकार का है और वह भी स्थानीय प्रशासन स्थानीय सरकार का, उसके लिए सेना के तीनों अंगों के प्रमुखों को क्यों सामने किया गया?

अग्निवीरों के लिए अलग से शपथ पत्र क्यों? क्या अग्निवीर सेना का हिस्सा नहीं?

आगजनी और उपद्रव नहीं करने संबंधी शपथपत्र अगर अग्निवीर बनने वालों को दिलायी जाने वाली है तो निश्चित रूप से यह सेना में मौजूद अनुशासन की परंपरा से अलग पहल होगी। क्या सेना में यह प्रयोग इसलिए किया जा रहा है कि 'अग्निवीर' सेना का हिस्सा नहीं हैं? यह संभव है कि अग्निवीरों के लिए शपथपत्र की नयी परंपरा शुरू की जा रही हो। एक बार फिर यह सवाल उठता है कि जब नौजवान अग्निवीर के लिए चुन लिए जाएं तो चाहे जो शपथपत्र लेना हो सेना ले सकती है। मगर, एक ऐसे समय में जब नियुक्ति प्रक्रिया भी शुरू नहीं हुई है और नौजवान आंदोलनरत हैं तो इसका जिक्र किसकी फिक्र करता दिख रहा है- नौजवानों की, सेना की या फिर सरकार की?

नौजवानों से बातचीत की जिम्मेदारी किसकी है?

देश में नौजवान अग्निपथ योजना के तहत भर्ती का विरोध कर रहे हैं तो नौजवानों से बातचीत की जिम्मेदारी किसकी है- सेना की या सरकार की? राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करने की जरूरत प्रधानमंत्री या गृहमंत्री को नहीं मिली है। सर्वदलीय बैठक बुलाकर भी शांति के लिए पहल की जा सकती थी, जो नहीं की गयी है।

महत्वपूर्ण है क्योंकि कृषि मंत्री समेत तमाम मंत्रियों की ओर से यह कहे जाते रहने के बावजूद कि ये वापस नहीं लिए जाएंगे, तीन कृषि कानून वापस लिए गए थे। नेता के साथ की परवाह आम जनता को बहुत नहीं होती, लेकिन उन्हें सेना प्रमुखों के साथ की परवाह जरूर रहती है।

पीछे क्यों रह गए 'अग्निपथ' का एलान करने वाले रक्षामंत्री?

दूसरा प्रश्न यह है कि क्या अग्निपथ योजना जैसा नीतिगत फैसला मोदी सरकार का है या कि सेना का? अगर सेना का होता, तो

आंदोलनकारी नौजवानों के साथ भी सहानुभूतिपूर्वक बात करने को सरकार सामने आ सकती थी, लेकिन सरकार ने इस विकल्प को भी नहीं आजमाया। नाराज़ नौजवान यही तो पूछ रहे हैं कि सेना में नियमित भर्ती क्यों रोक दी गयी है? अग्निवीर के रूप में चयन हो जाने के 4 साल बाद उनके भविष्य का क्या होगा?

इन सवालों का जवाब देने के लिए मुख्यमंत्रियों से कहलवाया जा रहा है कि अग्निवीरों को पुलिस बल में आरक्षण देंगे। असम रायफल्स और सीएपीएफ में 10 फीसदी आरक्षण की घोषणाएं की जा रही हैं।

क्यों नहीं कहती सरकार? अग्निवीर कभी नहीं होंगे बेरोजगार

केंद्र सरकार अगर अग्निपथ योजना से नाराज़गी को दूर करने के लिए सही मायने में पहल करना चाहती तो वह तमाम चिंताओं को समझते हुए एक उच्चस्तरीय बैठक में यह रोड मैप लेकर आ सकती थी कि अग्निवीरों में से कोई चार साल बाद बेरोजगार नहीं होगा और उनका समायोजन इस तरीके से इन जगहों पर होगा।

इसके बजाए केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने बताया है कि अग्निवीरों को ड्राइवर, धोबी, इलेक्ट्रिशियन, नाई और अन्य पेशे से जुड़ी ट्रेनिंग दी जाएगी। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने तो यहां तक कहा कि बीजेपी के मुख्यालय में सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत होगी तो सबसे पहले वे अग्निवीरों को प्राथमिकता देंगे।

मोदी सरकार के मंत्री किशन रेड्डी हों या फिर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय- इन्होंने नौजवानों की वाजिब चिंता पर अपनी मुहर ही लगायी है। इनकी बातों से सेना में भर्ती का सपना संजोए नौजवान अब अग्निवीर

बनने को लेकर और अधिक चिंतित होंगे। चार साल की पारी के बाद उनका क्या होगा- यह सवाल अब उन्हें अधिक डराएगा। सेना में भर्ती के आकांक्षी आंदोलनरत नौजवानों के लिए एक तरफ सेना के तीनों अंगों की ओर से अनुशासन का पाठ है, अग्निवीर बनने के लिए शर्तें हैं तो दूसरी तरफ अग्निवीर बन जाने के बाद उनके लिए ऐसे-

सवाल यह है कि सेना हजारों करोड़ की रकम को ऐसे अग्निवीरों पर व्यर्थ में खर्च क्यों कर रही है अगर उनका इस्तेमाल नाई, इलेक्ट्रिशियन, धोबी, ड्राइवर, चौकीदार, सिक्योरिटी गार्ड आदि के रूप में ही होना है

ऐसे जॉब के ऑफर हैं जिन्हें सुनकर ही नौजवानों को अपना काला भविष्य नज़र आ रहा है। ऐसे में नौजवान क्या करें? अग्निवीर बनें तो संकट और विरोध करें तो संकट।

हर अग्निवीर को चार साल में मिलेंगे

23.43 लाख रुपये

अग्निवीरों के लिए सालाना सैलरी पैकेज को अगर जोड़ें तो चार साल में उन्हें कुल 16,74,000 रुपये मिलने चाहिए। मगर, हाथ में 30 फीसदी काटकर मिलेंगे। इस हिसाब से उन्हें चार साल के अंत तक कुल 11,72,160 रुपये की राशि मिलेगी। सरकार की ओर से सेवा निधि में योगदान

और स्वैच्छिक योगदानों को जोड़कर कुल 10.04,0400 रुपये मिलेंगे। इस दौरान ब्याज समेत यह रकम 11.71 लाख रुपये होगी। यह रकम चार साल में 30 प्रतिशत कटौती के बाद मिलने वाली कुल रकम के लगभग बराबर है। इस तरह अग्निवीर को चार साल की सेवा के बाद मिलने वाली राशि और वेतन के रूप में प्राप्त राशि को जोड़कर देखें तो हरेक अग्निवीर को 23 लाख 43 हजार 160 रुपये मिलेंगे।

महज चार साल के लिए अग्निवीरों पर हजारों करोड़ का खर्च क्यों?

पहले दौर की भर्ती में 46 हजार अग्निवीरों की भर्ती होनी है। इनमें से दो तिहाई अग्निवीरों को सेना में नियमित सेवा का मौका नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह है कि 30 हजार 666 अग्निवीरों पर खर्च होने वाली राशि बेकार चली जाएगी। यह रकम होगी $30,666 \times 23,43,160 = 7185$ करोड़ 53 लाख 44 हजार 560 रुपये। इतनी बड़ी रकम का निवेश व्यर्थ चला जाएगा। अगर प्रशिक्षण आदि पर खर्च जोड़ें तो यह रकम कई गुणा ज्यादा होगी।

सवाल यह है कि सेना हजारों करोड़ की रकम को ऐसे अग्निवीरों पर व्यर्थ में खर्च क्यों कर रही है अगर उनका इस्तेमाल नाई, इलेक्ट्रिशियन, धोबी, ड्राइवर, चौकीदार, सिक्योरिटी गार्ड आदि के रूप में ही होना है। यह वो सवाल है जिसका जवाब लेकर सेना को या फिर सरकार को आना चाहिए।

(यह लेखक के अपने विचार हैं)



अगर सरकार पक्की है तो युवाओं की नौकरी भी पक्की हो

बुलेटिन ब्यूरो

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार की सेना में भर्ती की नई योजना 'अग्निपथ' के प्रति नौजवानों में व्यापक आक्रोश दिखाई दिया है। देश के भावी सैन्य बलों पर बल का दुरुपयोग करके युवाओं का मनोबल गिराया जा रहा है। क्या इसीलिए चुनी गई है लोकतंत्र में सरकार?

सत्ता के नशे में चूर भाजपा सरकार को यह दिखाई नहीं दे रहा है कि देश के कई प्रदेशों में भड़की विरोध की ज्वाला युवा विरोधी सत्ता को भस्म कर देगी।

श्री अखिलेश यादव ने कहा कि अग्निपथ से नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों

किया जा रहा है? देश की सुरक्षा कोई अल्पकालिक या अनौपचारिक विषय नहीं है। यह अति गम्भीर और दीर्घकालिक नीति की अपेक्षा करती है।

पिछले कई सालों से सेना में भर्ती नहीं हो पाई है और जिनकी भर्ती हुई वे कोविड से प्रभावित हो गई। अब उन्हें निरस्त किया जा रहा है। इससे जो लोग पास हो चुके हैं, जिनका मेडिकल हो चुका है, उन्हें जीवन भर के लिए नौकरी मिलना था अब 4 साल के लिए मिलेगी। फिर 4 साल के बाद क्या होगा? यह घोर अन्याय है। अगर सरकार पक्की है तो युवाओं की नौकरी भी पक्की होनी चाहिए।

आज देश की स्थिति इतनी विकराल है कि सेना जैसी अति संवेदनशील जगह में संविदा पर सैनिक रखे जा रहे हैं। भाजपा वाले नौकरियां आउटसोर्स कर युवाओं का भविष्य बर्बाद कर देंगे। आउटसोर्सिंग का

मतलब संविधान से दिया हक और सम्मान छीन लेना है।

ग्रामीण क्षेत्र के उनमें भी ज्यादातर किसानों के बेटे सेना में भर्ती होते हैं। भाजपा को गांव-गरीब और किसानों-नौजवानों के कल्याण में कोई रुचि नहीं है। अपनी जनविरोधी योजनाओं और नीतियों से भाजपा इनके हितों की अनदेखी करती है।

फौज में युवाओं के रोजगार की तमाम संभावनाएं हैं। फौज में उनकी संख्या में वृद्धि हो, अतः पहले जैसी सेना भर्ती प्रक्रिया लागू होनी चाहिए। नौजवानों की आशंकाओं का निराकरण किया जाना चाहिए। यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि भाजपा देश के लिए सैन्य बल तैयार करने में रुचि रखती है या अपने भाजपा कार्यालयों के लिए सिक्योरिटी गार्ड की ट्रेनिंग दिलवाने की योजना लागू करने जा रही है।

भाजपा सरकार देश को 'जय जवान-जय किसान' की जगह 'रुष्ट जवान और रुष्ट किसान' के बुरे हालात में ले आई है। सत्ता का ऐसा दुरुपयोग देश की राजनीति में किसी भी सरकार ने नहीं किया है। भाजपा पूरी तरह मनमानी पर तुली है। इससे भविष्य में देश के सामने संकट और भी ज्यादा गहरायेगा।



शोक संतप्त परिवारों से भेंट

बुलेटिन ब्यूरो



स

माजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने जून 2022 के माह में बस्ती और कन्नौज का दौरा कर पार्टी के दिवंगत नेताओं को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनके परिजनों से भेंट कर उन्हें ढाढस बंधाया। 14 जून को बस्ती में श्री अखिलेश यादव ने पूर्व विधायक जीतेन्द्र चौधरी को श्रद्धांजलि दी। श्री अखिलेश यादव ने दिवंगत विधायक जीतेन्द्र चौधरी के परिवार से मिलकर सांत्वना भी दी। बाद में उन्होंने कैसर पीड़ित सपा कार्यकर्ता

याकूब के गांव रामपुर पहुंच कर उनका हालचाल जाना। बाद में पत्रकारों से बातचीत के दौरान श्री अखिलेश यादव ने बस्ती की जनता का आभार देते हुए कहा कि पूरे जनपद वासियों ने अच्छा मतदान करते हुए समाजवादी पार्टी के पक्ष में अच्छा परिणाम दिया।

उन्होंने मीडिया से कहा कि हम सब जितने लोग खड़े हैं, जो सच्चा हिंदू होगा, कभी किसी के धर्म के खिलाफ नहीं बोलेगा। एक सच्चा हिंदू कभी भी किसी के भगवान या पैगम्बर के खिलाफ नहीं

बोल सकता। कानून-व्यवस्था पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार में लॉ अलग फेंक दिया गया है, आर्डर अलग चल रहा है। सरकार के पास महंगाई और बेरोजगारी का जवाब नहीं है, इसलिए सबको उलझा कर रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी जो किसानों, नौजवानों, महंगाई और बेरोजगारी के सवाल पर जनता हमारा साथ देगी। सत्तारूढ़ दल को जनता आने वाले लोकसभा चुनाव में जवाब देगी।

प्रदेश में चल रहे बुलडोजर राज के सवाल पर श्री अखिलेश यादव ने कहा कि









यह जो संस्कृति है कि हम कानून नहीं मानेंगे, नियम नहीं मानेंगे, हम संविधान नहीं मानेंगे, यह हमारे समाज और देश को कहां ले जाएगी। अगर लोग बिजली का बिल देते थे, हाउस टैक्स देते थे, पानी का बिल देते थे तो आखिरकार वह गैरकानूनी कैसे है और अगर किसी ने डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत घर गलत



भी बना लिया है, तो सरकार की योजना कंपाउंडिंग की है। सरकार उससे पैसे ले और नक्शा सही करे। सरकार ने कंपाउंडिंग नियम इसलिए बनाया है कि लोग उसका पैसा देकर अपना नक्शा सही करा लें।

विपक्ष के नेताओं की ईडी से जांच एवं पूछताछ के सवाल पर श्री अखिलेश

यादव ने कहा कि जितने भी हम राजनीति करने वाले लोग हैं उनको परीक्षा देनी पड़ती है। जैसे दसवीं की परीक्षा है, 12वीं की परीक्षा है वैसे ही ईडी भी एक परीक्षा है और यह मान लीजिए कि यह जो परीक्षा है यह डेमोक्रेसी की परीक्षा है।

वहीं श्री अखिलेश यादव ने 21 जून को कन्नौज का दौरा किया और सौरिख कस्बे

में स्थित सपा के जिला महासचिव रहे स्वर्गीय राम प्रकाश शाक्य के घर पहुंच कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। जहां उन्होंने परिवार के सदस्यों को सांत्वना देते हुए अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और राम प्रकाश शाक्य के निधन को सपा के लिए एक बड़ा झटका बताया।



आपातकाल

का अतीत और उसका भविष्य



फोटो स्रोत : गूगल

जयशंकर पांडेय

आपातकाल का अतीत बहुत कड़वा है लेकिन उसका भविष्य बहुत उज्ज्वल है। आपातकाल के बंदी होने के नाते पीड़ाजनक अहसास के साथ हिम्मत और जीत का अहसास भी होता है। लेकिन आज के दौर की पाबंदियों को देखकर लगता है कि भारत में आपातकाल का भविष्य बहुत उज्ज्वल है। सैंतालिस साल पहले देश ने और विपक्ष ने आपातकाल का जो अनुभव हासिल किया था वह 1977 में सत्ता परिवर्तन के बाद मिट गया था।

हालांकि 1980 जब फिर इंदिरा गांधी सत्ता में वापस आईं तो लगा कि जनता की स्मृतियां बहुत क्षणिक होती हैं। लेकिन इंदिरा गांधी की नई सरकार को अपनी गलतियों का अहसास था और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने जो भी सरकारें चलाई पूरी सतर्कता से चलाई। कांग्रेस पर इमरजेंसी का कलंक लगा हुआ था इसलिए वह हर चुनौती को लोकतांत्रिक ढंग से ही निपटने को तैयार रहती थी। फिर जनता को भी उसके चरित्र पर संदेह था इसलिए 1984 के अलावा कभी उसे पूर्ण या प्रचंड बहुमत दिया ही

नहीं।

बल्कि पिछले 39 सालों में चुनौतियों के बावजूद भारतीय लोकतंत्र एक जीवंत लोकतंत्र बनता हुआ दिखा। उस दौरान सामाजिक न्याय और क्षेत्रीय अस्मिता की शक्तियों का उदय हुआ और उन्होंने कभी दिल्ली की हैसियत घटाकर हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता और बंगलुरु की हैसियत बढ़ा दी तो कभी राष्ट्रीय दलों के आगे क्षेत्रीय दलों को महत्वपूर्ण बना दिया। यही वजह थी इस दौरान चंद्रशेखर, विश्वनाथ प्रताप सिंह, इंद्र कुमार गुजराल और देवगौड़ा जैसे

नेता प्रधानमंत्री बने तो, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद, बीजू पटनायक, एनटी रामराव, प्रकाश सिंह बादल, ज्योति बसु, शरद पवार, जयललिता, कांशीराम, मायावती, फारूक अब्दुल्ला, करुणानिधि, चंद्रबाबू नायडू, हरकिशन सिंह सुरजीत जैसे तमाम नेता ऐसे थे जो प्रधानमंत्री तो नहीं बने लेकिन जिनकी हैसियत बड़ी थी और जो दिल्ली की राष्ट्रीय राजनीति में वजन रखते थे। यह भारतीय लोकतंत्र का बहुरंगी स्वरूप था। डा मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे लेकिन सोनिया गांधी की राजनीतिक ताकत उनसे बड़ी थी। इस नए स्वरूप में लोकतंत्र भारत में अपने को नए ढंग से परिभाषित कर रहा था। गठबंधन की राजनीति का यह माडल जो

पश्चिम बंगाल और केरल से चलकर दिल्ली तक पहुंचा था और जिसे वीपी सिंह ने अपनाया था और बाद में अटल बिहारी वाजपेयी ने भी उसे अपनाकर उसके जनक होने का श्रेय लेना चाहा। हालांकि लगभग यही प्रयोग जयप्रकाश नारायण की प्रेरणा से चरण सिंह और मोरारजी देसाई ने भी किया था। लोकतंत्र के इस नए चरण को देखकर ही कांशीराम ने कहा था कि हमें केंद्र में मजबूत नहीं मजबूर सरकार चाहिए।

केंद्र की मजबूर सरकार के कारण देश कहीं से कमजोर नहीं हो रहा था। बल्कि देश की आर्थिक तरक्की हुई और नई प्रौद्योगिकी के साथ ढांचागत विकास भी हुआ। इसी दौरान सामाजिक न्याय की शक्तियां भी मजबूत

हुई और सैकड़ों सालों से रुका और जातिगत दलदल में धंसा सामाजिक न्याय का रथ भी चल निकला। सामाजिक न्याय के इसी रथ ने सांप्रदायिकता के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को बांधा और केंद्र की सत्ता को यह कहने को मजबूर किया कि वह अयोध्या, समान नागरिक संहिता और अनुच्छेद 370 के मुद्दे को नहीं उठाएगी। लेकिन कांग्रेस के कुप्रबंधन के कारण 2014 में लोकतंत्र का यह नया रूप विसर्जित हो गया।

2014 के बाद भारतीय लोकतंत्र का जो स्वरूप उभरा वह भले ही राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बनाकर सहकारी संघवाद लाने का दावा करे लेकिन उसने इंदिरा गांधी और उनके आपातकाल से ज्यादा सुनियोजित





तरीके से आपातकालीन कदम उठाने शुरू कर दिए। इस गठबंधन ने एक व्यक्ति को सारे अधिकार दे दिए और उसे देश का लाता बताकर जनता से उस पर मुहर लगवा ली। नारा लगा सबका साथ सबका विकास करने का, अच्छे दिन लाने का, सबके खाते में 15 लाख रुपए जमा करने का और करोड़ों नौकरियां देने का। लेकिन हकीकत में एक व्यक्ति को देश का अधिनायक बनाकर और एक पार्टी और उसके आनुसंगिक संगठनों को देशभक्त का खिताब देकर बाकी सभी को या तो भ्रष्ट बता दिया गया या फिर देशद्रोही। यानी इस सिरे से उस सिरे तक सब

शरीके जुर्म हैं आदमी या तो जमानत पर रिहा है या फरार। इंदिरा गांधी ने तो घोषित करके आपातकाल लगाया था और चुनाव टालने के अलावा संसद का कार्यकाल भी बढ़ाया था। इस निजाम ने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन वह सब कुछ किया जो इंदिरा गांधी ने किया था। बल्कि वे उससे भी आगे निकल गए। सांप्रदायिकता और नफरत के अश्वमेध का घोड़ा खोल दिया गया। वह माथे पर राष्ट्रवाद लिखकर पूरे देश में घूम रहा है। बहुसंख्यक समाज का रक्षक बताकर हर चुनाव में उसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया जाता है

और हर लोकतांत्रिक शक्ति को चुनौती देता है कि मेरा जो बिगाड़ना हो बिगाड़ लो। आंखों पर नफरत की पट्टी बांध कर सड़क पर खड़ी जनता यह समझ ही नहीं पा रही है कि यह घोड़ा राजा राम का है या दसानन रावण का। उसे पकड़ कर बांधना है या उसके पीछे पीछे दौड़ना है। मौजूदा निजाम की सबसे खास बात यह है कि उससे जुड़े कई लोग आपातकाल विरोधी संघर्ष में थे। इसीलिए जब भी कोई आपातकाल का स्मरण कराता था तो वे कहते थे कि उन्होंने तो आपातकाल से लड़कर देश में लोकतंत्र कायम किया था। इसलिए उनसे कम से कम तानाशाही लाने



फोटो स्रोत : गूगल

कर रही हैं किसी को कानोंकान खबर नहीं। घरों पर बुलडोजर चल रहे हैं, लोगों को बोलने और लिखने पर गिरफ्तार किया जा रहा है लेकिन उनके मुंह से शब्द भी नहीं निकलते। वे कभी कभी जागती हैं और गांव के आलसी पहरेदार की तरह से सीटी

मीडिया और कार्यपालिका की आम्बुड्समैन जैसी संस्थाएं या तो भयभीत हैं या फिर सत्ता के नशे में सोती रहती हैं। लोकपाल, केन्द्रीय सतर्कता आयोग, मानवाधिकार आयोग यह सब हैं लेकिन क्या कर रही हैं किसी को कानोंकान खबर नहीं

की अपेक्षा न करें। इंदिरा गांधी की सरकार ने 1976 में संविधान में 42 वां संशोधन करके लोकतांत्रिक संस्थाओं की शक्तियों को क्षीण किया था। इस निजाम ने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन वे संविधान और लोकतंत्र को अपनी उंगलियों पर नचा रहे हैं। क्योंकि उन्होंने बिना संशोधन किए ही लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर कर दिया है। मीडिया और कार्यपालिका की आम्बुड्समैन जैसी संस्थाएं या तो भयभीत हैं या फिर सत्ता के नशे में सोती रहती हैं। लोकपाल, केन्द्रीय सतर्कता आयोग, मानवाधिकार आयोग यह सब हैं लेकिन क्या

बजाकर और डंडा फटकार कर सो जाती हैं। लोकतंत्र की गठरी में चोर और ठग लग गए हैं। आज कांग्रेस जैसी पार्टी भी सर्वसत्तावाद की लाठी झेल रही है और अब उसके नेताओं को घंटों पूछताछ से गुजरना पड़ रहा है। उसके दफ्तर में घुसकर पुलिस पिटाई करती है। उसके नेताओं को सड़क पर घसीटा जा रहा है। यह स्थितियां बता रही हैं किसी भी दल के साथ ऐसा हो सकता है। मौजूदा निजाम का विरोध करने वाला कोई भी नागरिक या संगठन ऐसा नहीं है जिसे व्यवस्था के दमन की आंच न महसूस हो रही

है। कोई यूएपीए, कोई एनएसए, कोई राजद्रोह के अभियोग के तहत जेल में है और जमानत की संभावना दूर दूर तक नहीं है। जो नहीं है उस पर भ्रष्टाचार की तलवार लटक रही है। उससे भी चिंता की बात यह है कि यह सब लोकतंत्र के नाम पर हो रहा है। दुर्योग देखिए कि इन आठ सालों में धड़ाधड़ चुनाव हो रहे हैं। चाहे कोरोना हो, बाढ़ हो, गर्मी हो या हिमपात चुनाव आयोजन में कोई कमी नहीं है।

लेकिन लोकतंत्र लगातार कमजोर हो रहा है। नोटबंदी, जीएसटी और तालाबंदी, कृषि कानून के बाद अब अग्निपथ के नाम पर देश के नौजवानों और जनता को लथपथ कर दिया गया है। वह सेना को कमजोर किए जाने को देशभक्ति समझ रही है वैसे जैसे नोटबंदी को आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई मान रही थी। नजरबंदी के इस खेल से आगाह करने वाले हैं लेकिन जनता उनकी बात सुन नहीं रही है या सुनने नहीं दिया जा रहा है। जब तक समाज नहीं चेतेंगा तब तक इस देश में इस अघोषित आपातकाल का भविष्य उज्ज्वल ही है।

(यह लेखक के अपने विचार हैं)



भाजपा राज में अन्नदाता बेहाल

बुलेटिन ब्यूरो

फाइल फोटो

भा

रतीय जनता पार्टी और सरकार दोनों की मानसिकता किसान विरोधी है। किसानों की कीमत पर पूंजी घरानों का पोषण करने का उसका रिकॉर्ड जगजाहिर है। भाजपा सरकार द्वारा लाए गए तीन काले कृषि कानूनों के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। लखीमपुर खीरी में केन्द्रीय राज्य मंत्री के बेटे ने किसानों पर जीप चढ़ा दी जिसमें कई किसान मरे। इन सभी मामलों में भाजपा नेतृत्व पूरी तरह संवेदनशून्य बना रहा, लेकिन लगता नहीं कि भाजपा सरकार ने इस सबसे कोई सबक सीखा हो।

गन्ना किसानों का सहकारी चीनी मिलों पर अरबों रुपये बकाया है। खीरी की चीनी मिल पर गन्ना किसानों का अरबों रुपये बकाया है। भाजपा सरकार लगातार बकाया राशि के बारे में झूठ बोलती जा रही है। 14 दिन में गन्ने का भुगतान का दम भरने वाली भाजपा सरकार यह क्यों नहीं बताती कि किसानों का अब तक भुगतान क्यों नहीं हुआ? खीरी जिले में दो सहकारी और सात निजी क्षेत्र की चीनी मिले हैं। रुहेलखण्ड के बरेली, बदायूं, पीलीभीत और शाहजहांपुर जिलों में चीनी मिलों पर करोड़ों रुपये बकाया है। किसान बदहाली के शिकार हैं।

भाजपा सरकार के कर्जमाफी के झूठे दावों

तले दबे किसानों की जान जा रही हैं। बरेली के एक किसान ने साल 2008 में पम्पसेट लगाने के लिए 40 हजार रुपये का कर्ज लिया था। इस कर्ज पर चार गुना ब्याज 1.80 लाख रुपये की मांग पर बुजुर्ग किसान के होश उड़ गए और मिनटों में उसके प्राण निकल गए।

भाजपा सरकार ने किसानों को कई धोखे दिए हैं। अपने पांच साल पुराने संकल्प-पत्र (चुनाव घोषणा पत्र-2017) में किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था। वादा पूरा करने की अवधि 2022 थी। इस अवधि के 6 माह भी बीत रहे हैं पर अभी तक इस दावों की पूर्ति के कहीं कोई संकेत नहीं मिल

रहे हैं। किसानों का कुछ भला होने वाला नहीं है। किसानों की कर्जमाफी के वादे में भी धोखा हुआ। किसानों के बिजली बिल को आधा करने का भी भाजपा सरकार ने वादा किया था वह वादा भी झूठा साबित हुआ।

भाजपा पूंजीपति परस्त नीति के चलते ही इस वर्ष गेहूं की फसल की बिक्री क्रय केन्द्रों पर नहीं हुई। पांच बड़ी कम्पनियों ने किसानों से औने पौने दाम पर गेहूं खरीद लिया। सरकारी सांठगांठ के चलते राज्य सरकार के क्रय केन्द्र बहुत जगहों पर खुले नहीं, जहां खुले थे वहां कई-कई दिन तक खरीद नहीं हुई। किसान को समय से भुगतान का तो सवाल ही नहीं।

अब कंपनियां अपना मुनाफा कमाने के लिए महंगे दामों पर आटा बाजार में बेचेंगी। इससे आम आदमी प्रभावित हो रहा है। भाजपा चंद पूंजीपतियों के हाथों में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी बंधक बनाने की साजिश कर रही है।

समाजवादी पार्टी किसानों, गरीबों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है।

जनता का भाजपा सरकार की कुनीतियों के विरुद्ध दृढ़ता से प्रतिरोध जारी रहेगा क्योंकि झूठ और छल फरेब भाजपा-आरएसएस का एजेंडा है। तथ्यों को झुठलाकर, अपनी वाहवाही करने में भाजपा नेतृत्व को जरा भी संकोच नहीं होता है। भाजपा मूलतः पूंजीपतियों की पोषक पार्टी है। इसलिए गांव-गरीब की समस्याओं पर उसका ध्यान नहीं जाता है। किसान भाजपा राज में कर्ज तथा महंगाई की मार से परेशान होकर आत्महत्या करने को मजबूर हुआ है। सरकार ने किसानों की मदद करने के बजाय धोखा दिया है।

मुख्यमंत्री जी के कृषक विरोधी रवैया का

शर्मनाक नमूना लखीमपुर खीरी में देखने को मिला जहां भारतीय किसान यूनियन (टिकैत ग्रुप) के जिलाध्यक्ष श्री दिलबाग सिंह के वाहन पर दो बाइक सवारों ने गोलियां चलाई। श्री दिलबाग सिंह 3 अक्टूबर 2021 को हुए तिकोनिया काण्ड, जब केन्द्रीय राज्य मंत्री के बेटे द्वारा जीप से किसानों को कुचला गया था, के गवाह भी हैं। हमले की इस घटना में वे बाल-बाल बच गए। हमलावर उनकी हत्या करना चाहते थे। क्या यही जीरो टॉलरेंस है भाजपा सरकार का?

महंगाई के चलते खेती का लागत मूल्य बढ़ता जा रहा है। पेट्रोल-डीजल, खाद, बीज, कीटनाशक के दाम बढ़ने से खेती पर बोझ बढ़ा है। किसान की फसल को लागत से ड्योढ़ा लाभप्रद मूल्य मिलना चाहिए पर इस बार तो उसे फसल पर एमएसपी भी नहीं मिल सकी

भाजपा ने पांच साल पहले अपने चुनाव घोषणा-पत्र, जिसे संकल्प-पत्र नाम दिया गया था, में किसानों के लिए कई वादे किए थे लेकिन आज तक भाजपा सरकार उस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा सकी। भाजपा लगातार किसानों से झूठे वादे करके जनता

की निगाह में अपनी विश्वसनीयता खो रही है।

महंगाई के चलते खेती का लागत मूल्य बढ़ता जा रहा है। पेट्रोल-डीजल, खाद, बीज, कीटनाशक के दाम बढ़ने से खेती पर बोझ बढ़ा है। किसान की फसल को लागत से ड्योढ़ा लाभप्रद मूल्य मिलना चाहिए पर इस बार तो उसे फसल पर एमएसपी भी नहीं मिल सकी। किसानों के हजारों करोड़ रुपये के बकाये को छुपाने के लिए भाजपा सरकार आंकड़ों का मकड़जाल बिछा रही है।

समाजवादी सरकार किसानों की सरकार थी। राज्य के बजट में बजट का 75 प्रतिशत बजट केवल ग्रामीण विकास, गांव और खेती के विकास के लिए रखा गया था। समाजवादी सरकार में कामधेनु योजना शुरू हुई थी। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा था। कामधेनु और पोल्ट्री फार्म पर समाजवादी सरकार सब्सिडी देती थी। भाजपा सरकार से इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती है। यही नहीं समाजवादी सरकार में किसानों को मुफ्त सिंचाई और कर्ज माफी के साथ समय से खाद, बीज, कीटनाशक उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था की गई थी। इससे किसान को फसल के समय इधर-उधर दौड़ना नहीं पड़ता था।



सपा कार्यकर्ता कमियों से सबक लें

-अखिलेश

बुलेटिन ब्यूरो

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि पांच वर्ष और दो महीनों की भाजपा सरकार के रवैये में कोई बदलाव नहीं आया है। प्रदेश में विकास और निवेश की झूठी कहानी गढ़ी जा रही है। नौजवानों और किसानों के साथ धोखा किया गया है। कानून

व्यवस्था का कहीं अता पता नहीं है। राज्य की भोली-भाली जनता को झूठे किस्से-कहानी सुनाकर गुमराह किया जा रहा है। भाजपा का यह पुराना एजेण्डा है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि वे भाजपा के दुष्प्रचार का हर स्तर पर मजबूती से पर्दाफाश करें।

श्री अखिलेश यादव ने दिनांक 4 जून को

सपा मुख्यालय, लखनऊ में विधानसभा चुनाव-2022 में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों, प्रकोष्ठों के राष्ट्रीय एवं प्रदेश अध्यक्षों तथा कुछ प्रमुख जिलाध्यक्षों की बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। बैठक में विधानसभा चुनाव की समीक्षा के साथ सन् 2024 के लोकसभा और 2027 के विधानसभा चुनावों की रणनीति पर भी चर्चा हुई।



श्री यादव ने कहा कि भाजपा को संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित समाजवाद, लोकतंत्र तथा पंथनिरपेक्षता पर विश्वास नहीं है। भाजपा संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का काम कर रही है। गांव-गरीब उसकी प्राथमिकता में नहीं है। भाजपा समाज में नफरत और तनाव फैला कर राज कर रही है। भाजपा की इस राजनीति से सभी को सावधान रहना है। समाजवादी पार्टी संविधान और सामाजिक सौहार्द के लिए प्रतिबद्ध है। जनता से भी अपील है कि वह शांति व्यवस्था बनाएं रखे और माहौल बिगाड़ने वालों के इरादों को सफल न होने दे।

श्री यादव ने कहा कि लोकतंत्र में चुनाव आयोग की भूमिका निष्पक्ष नहीं रही। उसने चुनाव के दौरान पार्टी की शिकायतों का समुचित संज्ञान नहीं लिया। श्री यादव ने कहा इस बार चुनावों में मतदाता सूची में भी काफी गड़बड़ियां पाई गईं। तमाम मतदाताओं के नाम गायब थे

श्री अखिलेश यादव ने कहा कि सन् 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ा है। इस चुनाव में सभी प्रत्याशी मजबूती से लड़े। चुनाव में हार-जीत होती रहती है। कई प्रत्याशी बहुत कम अंतर से हारे हैं। प्रशासन का दुरुपयोग करके कई विधानसभा क्षेत्रों के चुनाव परिणामों को प्रभावित किया गया।

श्री यादव ने कहा कि लोकतंत्र में चुनाव आयोग की भूमिका निष्पक्ष नहीं रही। उसने चुनाव के दौरान पार्टी की शिकायतों का समुचित संज्ञान नहीं लिया। श्री यादव ने कहा इस बार चुनावों में मतदाता सूची में भी काफी गड़बड़ियां पाई गईं। तमाम मतदाताओं के नाम गायब थे। कई बूथों पर पीठासीन अधिकारियों की भूमिका भी संदिग्ध रही। आरएसएस ने भी अफवाहें फैलाने और दुष्प्रचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी।

श्री अखिलेश यादव ने कहा कि विधानसभा-2022 के चुनाव में जो कमियां दिखी उनसे सबक लेना चाहिए। आगे से मतदान के प्रति जागरूकता फैलाते हुए मतदान प्रतिशत बढ़ाने का प्रयास होना चाहिए। उन्होंने अभी से सन् 2024 में लोकसभा चुनाव और 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियां करने, संगठन को मजबूती देने तथा बूथ स्तर पर चिह्नित करके वोट बढ़ाने पर विशेष बल दिया।



भाजपा के एजेंडे में फंसने से बचें अल्पसंख्यक

बुलेटिन ब्यूरो

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने अल्पसंख्यक भाइयों सहित सभी समाजवादी कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे भाजपा के किसी एजेंडा में न फंसकर सन् 2024 के लोकसभा चुनावों में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीतने का लक्ष्य लेकर एकजुट हों।

उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किया है और सन् 2022 के विधानसभा चुनावों में अल्पसंख्यक भाइयों ने एकमुश्त समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान किया जिसके लिए उन्हें धन्यवाद।

श्री अखिलेश यादव दिनांक 2 जून को समाजवादी पार्टी मुख्यालय लखनऊ के डॉ

लोहिया सभागार में समाजवादी अल्पसंख्यक सभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित कर रहे थे जिसकी अध्यक्षता मौलाना इकबाल कादरी राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी अल्पसंख्यक सभा तथा संचालन महासचिव मो. यामीन खान ने किया।

समाजवादी अल्पसंख्यक सभा की बैठक में



वक्ताओं ने श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए भरोसा दिलाया कि अल्पसंख्यक पूरी तरह से उनके साथ हैं और रहेंगे। आगामी लोकसभा चुनावों में भी उनका समर्थन समाजवादी पार्टी को मिलेगा।

श्री अखिलेश यादव ने कहा कि आज देश भाजपा की कुनीतियों के चलते तमाम समस्याओं से जूझ रहा है। देश की अर्थव्यवस्था में गिरावट आई है। अमीर गरीब के बीच असमानता बढ़ी है। महंगाई भ्रष्टाचार से लोग परेशान है। नोटबंदी-

जीएसटी ने व्यापार चौपट कर दिया है। किसान, नौजवान के हितों की उपेक्षा की जा रही है।

श्री यादव ने कहा कि भाजपा नफरत फैलाने और समाज को बांटने के एजेंडा पर काम कर रही है। संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है। महत्वपूर्ण पदों पर आरएसएस के लोगों को बिठाया जा रहा है। वह देश की गंगा जमुनी संस्कृति को तोड़ने और आपसी सौहार्द को नष्ट करने में लगी है उसकी इन नीतियों से देश के एक बड़े वर्ग में भय और असुरक्षा की भावना है।

उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी सामाजिक सद्भाव और सबको साथ लेकर विकास के रास्ते पर चलने के लिए प्रतिबद्ध है। अपनी इसी विचारधारा के साथ हम सभी चुनौतियों से निबटेंगे।

समाजवादी अल्पसंख्यक सभा की बैठक में सर्वश्री मौलाना इरफान उल हक कादरी, सरताज चौधरी, आफताब कुरैशी, मोहम्मद यूनुस, सरदार सुरेन्द्र सिंह, डेनियल साइमन, इसरार चौधरी आदि की उपस्थिति उल्लेखनीय रही।

सपा का अन्य राज्यों में विस्तार तेज

गुजरात में कार्यकारिणी का गठन



बुलेटिन ब्यूरो

समाजवादी पार्टी ने अन्य राज्यों में विस्तार की अपनी रणनीति को गति देते हुए गुजरात में पार्टी की कार्यकारिणी का गठन कर दिया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने गुजरात समाजवादी पार्टी में अध्यक्ष श्री देवेन्द्र उपाध्याय (वडोदरा), उपाध्यक्ष श्री अभिलाष धनेशा (वडोदरा), श्री विजय

कुमार यादव (सिलवस्सा) तथा श्री अहीर मयूर सोलंकी (राजकोट) जबकि प्रमुख महासचिव श्री राम सेवक साहनी (वडोदरा) और श्री हसीब अंसारी (वडोदरा) को कोषाध्यक्ष नामित किया है। इनके अलावा सर्वश्री किरन कन्सारा (अहमदाबाद), भीखा भाई हरभा (जामनगर) एवं अरविन्द चौबे (अहमदाबाद) महासचिव नामित हुए हैं।

इनके अतिरिक्त प्रदेश कार्यकारिणी में 25 सचिव और 67 सदस्य बनाए गए हैं।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि गुजरात में भाजपा के सत्ताकाल के 25 वर्ष घोर निराशाजनक रहे हैं। किसानों-नौजवानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों की आय में दो दशकों में कोई गुणात्मक अंतर नहीं आया



मध्य प्रदेश में पदाधिकारी नामित

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव द्वारा मध्य प्रदेश सपा संगठन में प्रदेश पदाधिकारी नामित किए गए हैं। समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश संगठन में सर्वश्री रामायण सिंह पटेल प्रदेश अध्यक्ष (रीवा), मूलचन्द्र उर्फ बन्ते यादव (इंदौर) एवं विश्वनाथ सिंह मरकाम

प्रदेश उपाध्यक्ष (सिंगरौली), डॉ मनोज यादव प्रदेश प्रमुख महासचिव (भोपाल), राकेश सिंह बघेल प्रदेश महासचिव (शहडोल) तथा आशीष पटेल (कुशवाहा) प्रदेश सचिव (छतरपुर) नामित किए गए हैं।

है। सूरत, बड़ौदा, अहमदाबाद, गांधीनगर, जामनगर, राजकोट सहित पूरे गुजरात में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं है। गांवों में महिलाएं दूर-दूर से पीने का पानी लाने के लिए मजबूर हैं। बहुत से लोग खरीद कर पानी पीते हैं।

श्री यादव ने कहा कि पांच महानगरों के अतिरिक्त पूरा गुजरात बंजर और उजाड़ है। पांच प्रतिशत चकाचौंध के अतिरिक्त बाकी 95 प्रतिशत गुजरात अंधकार में डूबा हुआ है। गांव में सड़कें नहीं हैं। बिजली का संकट बरकरार है। चिकित्सा व्यवस्था बदहाल है। ठेकेदारी प्रथा से आंशिक रोजगार मिला है। प्राथमिक शिक्षा की स्थिति बदतर है। भाजपा राज में विकास कुछ बड़े शहरों तक ही केन्द्रित है। जनता भाजपा राज से ऊबी हुई है। लोग भाजपा से मुक्ति चाहते हैं। समाजवादी पार्टी अब गुजरात मॉडल के छलावा का पर्दाफाश करेगी।





साफ़ और बेबाक

Akhilesh Yadav 

@yadavakhilesh

Socialist Leader of India. Chief Minister of UP (2012 - 2017)

Akhilesh Yadav 
@yadavakhilesh

देश के भावी सैन्य बलों पर बल का दुरुपयोग करके भाजपा सरकार युवाओं का मनोबल गिरा रही है। 'भारत माता' का उद्धोष झूठे दिखावे का नहीं; सच्ची देशभक्ति का प्रतीक होना चाहिए।

सेना का ठेकेदारीकरण देश और सच्चे देश भक्त युवाओं के लिए विश्वासघात के समान है।

फ़ौज आउटसोर्स का विषय नहीं है।

[Translate Tweet](#)



Akhilesh Yadav 
@yadavakhilesh

'अग्निपथ' की नीति सरकार ने बनायी है अतः सरकार व सत्ताधारी दल के प्रवक्ता किसी और को आगे न करें।

अमीर उद्योगपतियों की आय की सुरक्षा से अधिक ज़रूरी है देश की सुरक्षा इसीलिए जो भी बजट कम पड़ रहा है उसके लिए सरकार कॉरपोरेट पर अतिरिक्त कर लगाए परंतु देश की सुरक्षा के साथ समझौता न करे।

Akhilesh Yadav 
@yadavakhilesh

भाजपा जिस तरह अपने समर्थकों से 'अग्निवीर' के तथाकथित फ़ायदे गिनवाने में लगी है, उससे अच्छा होगा कि भाजपा अपने उन सदस्यों-समर्थकों की सूची जारी करे जो इस योजना में अपने बच्चों को भेज रहे हैं। प्रवचन देने से अच्छा है भाजपाई खुद उदाहरण पेश करें।

भाजपा युवाओं का अपमान बंद करे।

Akhilesh Yadav 
@yadavakhilesh

राय
सलाह
मंत्रणा
सम्मति
मशवरा
परामर्श
विचार-विमर्श
संयुक्त निर्णय
सामूहिक बैठक

ये लोकतांत्रिक शब्द भाजपाई शब्दकोश में नहीं हैं। तभी बार-बार देश पर मनमानी भरे फ़ैसले थोपे जा रहे हैं, जिससे देश की ऊर्जा व जनशक्ति सरकार की जनविरोधी नीतियों व योजनाओं के विरोध में ही बर्बाद हो रही है।

Akhilesh Yadav 
@yadavakhilesh

कन्नौज में सपा काल में प्रस्तावित विश्वस्तरीय 'इत्र पार्क' राजनीतिक विद्वेष का शिकार होकर वीरान पड़ा है। उग्र सरकार प्रदेश व कन्नौजवासियों की भलाई के लिए इसे तुरंत बनाए।

खुशबू से नफ़रत भला कौन कर सकता है।

[Translate Tweet](#)



Akhilesh Yadav 
@yadavakhilesh

अयोध्या में दिनदहाड़े गर्भवती शिक्षिका की चाकुओं से गोदकर की गयी हत्या का समाचार दुखद है। श्रद्धांजलि!

अयोध्या में जगह-जगह सुरक्षा बलों की उपस्थिति के बाद भी ऐसी हत्या, शासन-प्रशासन को अपराधियों की खुनी चुनौती है। भाजपा के राज में शिक्षक सरकार और अपराधियों दोनों के निशाने पर हैं।

Akhilesh Yadav 
@yadavakhilesh

प्रतापगढ़ में कोतवाली के पास ही एक सिपाही की हत्या का समाचार उग्र में क़ानून-व्यवस्था की स्थिति को बताने के लिए काफ़ी है।

मृतक सिपाही को श्रद्धांजलि व इंसान की माँग!

ऐसी घटनाओं से पुलिस का मनोबल गिरता है और दबंगों का बढ़ता है।

निंदनीय!

Akhilesh Yadav 
@yadavakhilesh

भाजपा के राज में लोकतंत्र की हत्या की क्रॉनॉलॉजी:

- नामांकन के समय चीरहरण
- नामांकन निरस्त कराने का षड्यंत्र
- प्रत्याशियों का दमन
- मतदान से रोकने के लिए दल-बल का दुरुपयोग
- काउंटिंग में गड़बड़ी
- जन प्रतिनिधियों पर दबाव
- चुनी सरकारों को तोड़ना

ये है आज़ादी के अमृतकाल का कड़वा सच!

Akhilesh Yadav 
@yadavakhilesh

देश की सुरक्षा कोई अल्पकालिक या अनौपचारिक विषय नहीं है, ये अति गंभीर व दीर्घकालिक नीति की अपेक्षा करती है। सैन्य भर्ती को लेकर जो खानापूति करनेवाला लापरवाह रवैया अपनाया जा रहा है, वो देश और देश के युवाओं के भविष्य की रक्षा के लिए घातक साबित होगा। 'अग्निपथ' से पथ पर अग्नि न हो।

Akhilesh Yadav 
@yadavakhilesh

ये कहाँ का इंसान है कि जिसकी वजह से देश में हालात बिगड़े और दुनिया भर में सख्त प्रतिक्रिया हुई वो सुरक्षा के घरे में हैं और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को बिना वैधानिक जाँच पड़ताल बुलडोज़र से सज़ा दी जा रही है।

इसकी अनुमति न हमारी संस्कृति देती है, न धर्म, न विधान, न संविधान।



Following



Akhilesh Yadav @yadavakhilesh

‘अग्निपथ योजना’ की वजह से उप्र के एक युवा विकास पटेल की आत्महत्या की खबर बेहद दुखद है।

भावपूर्ण श्रद्धांजलि!

ये देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारी युवा शक्ति कुछ लोगों के दंभ की बलि चढ़ रही है। शायद विकास की ये शहादत ही सत्ताधारियों को उनके अहंकार की नींद से जगा पाए।



Akhilesh Yadav @yadavakhilesh

उठने चाहिए ऐसी हवालात पर सवालात नहीं तो इंसान खो देगा अपना इकबाल

- यूपी हिरासत में मौतों के मामले में न. 1
- यूपी मानवाधिकार हनन में अव्वल
- यूपी दलित उत्पीड़न में सबसे आगे

[Translate Tweet](#)



Akhilesh Yadav @yadavakhilesh

ब्राजील में आयोजित ‘डेफ ओलंपिक’ में बैडमिंटन की टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर देश को गौरवान्वित करने वाली गोरखपुर की गोल्डन गर्ल आदित्या यादव को 5 लाख रुपए की राशि प्रोत्साहन स्वरूप देकर हम सब हर्षित हैं।

सरकार आदित्या को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देकर सम्मानित करे।

[Translate Tweet](#)



Akhilesh Yadav @yadavakhilesh

भारत की महान वीरगंगा एवं कुशल शासक महारानी अहिल्याबाई होल्कर जी की जन्म जयंती पर उन्हें कोटिशः नमन।

[Translate Tweet](#)



Akhilesh Yadav @yadavakhilesh

आज़ादी के अमृत महोत्सव में।

सच्ची स्वतंत्रता का महोत्सव निरंतर रहना चाहिए...

[Translate Tweet](#)



Akhilesh Yadav @yadavakhilesh



Akhilesh Yadav @yadavakhilesh

अपने देश के नागरिकों की अपमानजनक उपमा करना संकीर्ण सोच का प्रतीक है। जहाँ लोगों के पास खाने को अन्न नहीं है, वहीं सत्ताधारी खुद कालीन का ऐश्वर्य-भोग करने की बात कह रहे हैं। ये विभेद जनतांत्रिक-भ्रष्टाचार है।

इतिहास गवाह है कि जनता अहंकारी सत्ता के नीचे से कालीन खींच लेती है।

[Translate Tweet](#)

अमर उजाला

बरेली

www.ujala.com

‘हमारा अनाज खाकर मोटे हुए चूहे अब काट रहे हैं हमारा ही कालीन’

खेतों-मुक्त अनाज का लाभ लेने वाले एक ही वर्ग के 40 फीसदी लोग पर भाजपा को वोट नहीं देने



Akhilesh Yadav @yadavakhilesh

भाजपा सोचती है कि लोग फ़ौज में नौकरी करने जाते हैं, दरअसल युवा देश-प्रेम के जज़्बे से सेना में जाते हैं, लेकिन ये वो क्या जानें जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन तक में हिस्सा ही न लिया हो।

भाजपा सरकार देश को ‘जय जवान जय किसान’ से ‘रुष्ट जवान रुष्ट किसान’ के बुरे हालातों में ले आई है।

[Translate Tweet](#)



Akhilesh Yadav @yadavakhilesh

ED का मतलब अब ‘Examination in Democracy’ बन गया है। राजनीति में विपक्ष को ये परीक्षा पास करनी होती है। जब सरकार स्वयं फ़ेल हो जाती है तब वो इस परीक्षा की घोषणा करती है। जिनकी तैयारी अच्छी होती है वो न तो लिखा-पढ़ी की परीक्षा से डरते हैं, न मौखिक से... और कभी डरना भी नहीं चाहिए।

वाह, गिर गया घर, मुबारक-मुबारक!
हुकूमते बुलडोज़र मुबारक-मुबारक!
ईंट गिरी, दीवार गिरी, एक पूरी उम्र गिरी
और हंसते रहे बर्बर- मुबारक मुबारक!
ये बदहवास बीमार सा मुल्क का चेहरा
पसीने से तरबतर, मुबारक मुबारक!
न मुल्क न मज़हब न इंसान की फ़िक्र
सत्ता के ये सौदागर मुबारक मुबारक!

- प्रियदर्शन

